● वर्ष-4
● अंक-123
रायपुर, गुरुवार 02 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» नववर्ष को जिन्दगी का सबसे बड़ा वर्ष

नए साल के पहले दिन सचिवों और विभागाध्यक्षों को दो टूक

प्रशासनिक काम-काज में ढिलाई बर्दाश्त नहीं:साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नए साल के पहले दिन ही मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर शासकीय काम-काज में पारदर्शिता और कसावट लाने के साथ-साथ आमजनता से जुड़े मामलों का तत्परतापूर्वक त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में दो टूक कहा कि प्रशासनिक काम-काज में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को टीम भावना के साथ काम करना होगा।मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वर्ष 2024 में हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। रजत जयंती वर्ष का छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व है, इसलिए बहुत उत्साह से निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष अभियान संचालित कर लंबित फाइलों को तत्परता से निराकृत करने की हिदायत दी। उन्होंने मंत्रालय सहित सभी ऑफिसों में ई-ऑफिस की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे स्वयं सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को अपने विभाग की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर महीने वर्चुअल समीक्षा के साथ ही हर 3 महीने में भौतिक समीक्षा भी की जाए। साथ ही बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने का प्रयास करें और मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी की समस्याओं का समय पर निराकरण होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हमारा फोकस होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी निवेश का बहुत अच्छा माहौल बना है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-2030 की पूरे देश में सराहना की जा रही है। नई औद्योगिक नीति का लाभ निवेशकों को मिले, इसका विशेष ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत एक साल में हमने नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी पाई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में हम कामयाब हुए हैं। शासन की योजनाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक ले जाने की आवश्यकता है। नियद नेल्ला नार योजना का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिले, यह बहुत जरूरी है। नक्सली क्षेत्र में बहुत से सुरक्षा कैंप हमने खोले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि संबंधित विभाग के कार्य जो नियद नेल्ला नार योजना के तहत आते हैं, वे त्वरित गति से इन क्षेत्रों में पूर्ण हों। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाना सेवा का कार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के प्रभारी सचिव हर 2 महीने में जिलों का दौरा करें। इस दौरान वे जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में जाएं और फील्ड की जानकारी लें, तभी जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। उन्होंने प्रभारी सचिवों को अपने जिले के भ्रमण के दौरान वहां की स्थिति के के सम्बन्ध में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव अनिवार्य रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए।

नए साल पर तोहफा

खाद पर सब्सिडी बढ़ी

मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला

नईदिल्ली। नए साल में मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक किसानों के नाम रही है। साल के पहले दिन बुधवार को हुई बैठक में डीएपी फर्टिलाइजर के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके तहत फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा यह सब्सिडी (स्पेशल पैकेज) 31 दिसंबर 2025 तक दी गई है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि किसानों को डीएपी का 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। यह %वन टाइम पैकेज% काफी महत्वपूर्ण है। पड़ोस के देशों में डीएपी का 50 किलो का बैग तीन हजार रुपये से ज्यादा में मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भले ही

कैसे भी स्थिति आ जाए हमें अपने किसानों को सुरक्षित करना है। उनके ऊपर बोझ नहीं डालना है।

उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि डीएपी के नाम पर कुछ लोग किसानों को ठगने का प्रयास करेंगे। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि अगर कोई ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस पैकेज पर लगभग 3,850 करोड़ रुपये की लागत होगी। साल 2014 से लेकर अब तक कोविड-19 का वह दौर भी आया जब स्थिति काफी खराब थी। लेकिन, हमारी सरकार और पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव का खामियाजा न उठाना पड़े। 2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये थी जो 2004-14 के दौरान दी गई सब्सिडी से दोगुनी से भी अधिक है।

कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए न रोकी जा सकने वाली प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इसके अलावा, योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर!

नए साल की शुरुआत ही में ग्राहकों को बड़ा तोहफा मिल गया है। 1 जनवरी से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है, जिससे नए साल में लोगों को राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,818.5 से घटकर 1,804 हो गई है। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बुधवार को ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में भी 1.54 फीसदी की गिरावट आई। हाल ही में कीमतों में कटौती एलपीजी की कीमतों में लगातार पांच महीनों की बढ़ोतरी के बाद की गई है। पांच बार की गई बढ़ोतरी में एलपीजी की कीमतों में 19 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम 172.5 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि, अगस्त से पहले, कीमतो में 4 बार की कटौती के कारण 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 148 रुपये की कमी आई थी।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर दिया जोर

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवांगांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।

कांग्रेस का जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान

नईदिल्ली। कांग्रेस 3 जनवरी को सभी ब्लॉकों, जिलों और राज्यों में अपना जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 26 जनवरी को महू में एक सार्वजनिक रैली में समाप्त होगा। यह अभियान 27 दिसंबर को शुरू किया जाना था। लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के निधन और उनके सम्मान में सात दिवसीय शोक की घोषणा के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया था। अभियान आयोजित करने का निर्णय 26 दिसंबर को बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की आखिरी बैठक में लिया गया था।

3 जनवरी को आगाज 26 को समापन

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 26 दिसंबर के सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव के कार्यान्वयन को सिंह के प्रति गहरे सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का आदी होने में अभी और समय लगेगा कि वह अब हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान 3 जनवरी, 2025 को ब्लॉकों, जिलों और राज्यों में फिर से शुरू होगा, जिससे 26

जनवरी, 2025 को डॉ. अंबेडकर की जन्मभूमि महू में रैली होगी, जो कि 75वीं वर्षगांठ भी है।

सीडब्ल्यूसी ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि कांग्रेस संविधान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तदनुसार, सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में कहा गया है, कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी, जो 27 दिसंबर को बेलगावी में एक रैली से शुरू होगी और 26 जनवरी को महू में एक रैली में समाप्त होगी।

प्रमुख समाचार

26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द लाया जाएगा भारत!

मुंबई। देश में 26/11 मुंबई हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मुंबई क्राइम ब्रांच और एनआईए के विश्वसनीय सूत्रों ने बुधवार को पुष्टि की कि आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से जल्द भारत लाया जाएगा। पिछले साल अगस्त में अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत द्वारा राणा की अपील खारिज किए जाने के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज हो गई है।एजेंसियां अगर नए साल में तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाब होती हैं, तो यह एक बड़ी सफलता होगी। अमेरिकी कोर्ट ने अगस्त 2024 में फैसला सुनाते हुए भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने की मंजूरी दी थी, लेकिन मामला कागजी कार्रवाई में ही अटका रहा। भारतीय एजेंसियों ने कोर्ट में सभी सबूत पेश किए थे, जिसके बाद कोर्ट ने मंजूरी दी थी।अमेरिका के एफबीआई ने राणा को साल 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव के तौर पर भारत में काम कर रहा था।

संयुक्त किसान मोर्चा ने गठित कमेटी से मिलने किया इनकार

नईदिल्ली। सेवानिवृत्त न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट की समिति ने एसकेएम को 3 जनवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। किसान संगठन ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और बैठक के दौरान एमएसपी और अन्य संबंधित मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, इसकी पुष्टि राष्ट्रीय समन्वय सदस्य रमिंदर सिंह पटियाला ने की। संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कोर्ट का दखल हमें मंजूर नहीं है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने पहले ही कमेटी से बात करने से मना कर दिया था। एसकेएम के मुताबिक मोर्चा न्यायालय के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि किसान केंद्र सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जहां न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट की समिति ने एसकेएम को 3 जनवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। किसान संगठन ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में बनेगा कॉलेज

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज की नींव रख सकते हैं। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही उनके पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय परिसरों के दो नए परिसरों की नींव रखने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री 3 जनवरी को आधारशिला रखेंगे। सावरकर के नाम पर कॉलेज को डीयू की कार्यकारी परिषद ने 2021 में मंजूरी दे दी है। इसे 140 करोड़ रुपये की अस्थायी लागत पर बनाया जाएगा। सूत्रों ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय ने प्रधान मंत्री को निमंत्रण दिया है, और प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, सूरजमल विहार में प्रस्तावित पूर्वी परिसर 373 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा। पश्चिमी परिसर द्वारका में बनाया जाएगा और इस पर 107 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। 2021 में, डीयू की कार्यकारी परिषद ने दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर एक कॉलेज का नाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर केंद्र ने शुरू की प्रक्रिया

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभावित स्थलों के सुझाव उनके परिवार के साथ साझा किए गए हैं, जिनसे निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक स्थान का चयन करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक, स्मारक के लिए राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के पास लगभग 1 से 1.5 एकड़ जमीन प्रस्तावित की गई है। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी पहले ही इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं, मनमोहन सिंह के परिवार को कुछ विकल्प दिए गए हैं। नई नीति के तहत स्मारक के लिए जमीन केवल किसी ट्रस्ट को ही आवंटित की जा सकेगी। इसलिए, परियोजना शुरू करने के लिए एक ट्रस्ट का गठन एक शर्त है। एक बार ट्रस्ट स्थापित हो जाने के बाद, यह भूमि आवंटन के लिए आवेदन करेगा, और निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसी भी संभावना है कि स्मारक राजघाट के पास स्थित हो सकता है, जहां जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के अंतिम विश्राम स्थल स्थित हैं।

बांग्लादेश से बहुसंख्यक समुदाय के लोग आ रहे भारत

नईदिल्ली। दक्षिणी राज्य में छ्रस्ब्य का शासन है, जो कि इंडिया गुट का एक घटक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति के कारण उस देश में कपड़ा उद्योग का पतन हो गया है। मजदूर, जो वहां बहुसंख्यक हैं लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में आशांति के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाल में बांग्लादेश से राज्य में आने वाले लोगों में ज्यादातर पड़ोसी देश के 'बहुसंख्यक समुदाय' के लोग हैं, न कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं। उन्होंने दावा किया कि जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वे मुस्लिम-बहुल बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के श्रमिक हैं, जो वहां संकट के बाद खराब स्थिति में हैं, और वे उसी क्षेत्र में शामिल होने के लिए तमिलनाडु जाना चाहते हैं। दक्षिणी राज्य में छ्रस्ब्य का शासन है, जो कि इंडिया गुट का एक घटक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति के कारण उस देश में कपड़ा उद्योग का पतन हो गया है। मजदूर, जो वहां बहुसंख्यक हैं लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तमिलनाडु में कपड़ा उद्योगों में जाने के लिए देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली और बिहार पर रहेगी सबकी नजर

2025 में इंडिया गठबंधन का बढ़ेगा कद या एनडीए का दिखेगा दम

नईदिल्ली। राजनीतिक दंगलों वाला 2024 खत्म हो चुका है। राजनीतिक दलों के लिए 2024 में जहां कुछ खुशियां और कुछ गम रहे। वहीं 2025 की चुनौतियां अब शुरू होती दिखाई दे रही है। 2025 राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2025 में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की कड़ी परीक्षा होती हुई दिखाई देगी। सभी की निगाहें हाल ही में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर रहेंगे। साथ ही साथ साल के आखिर में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे जो राजनीतिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2015 में जब देश में प्रचंड मोदी लहर थी, उसके बावजूद भी बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

यह वही दोनों राज्य हैं जिसने समय समय पर विपक्ष को बड़ी संजीवनी दी है। हालांकि, यह बात भी सही है कि नीतीश कुमार की पलटीमार राजनीति सरकार और विपक्ष का समीकरण बदलते रहता है। दिल्ली और बिहार को लेकर भाजपा रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए राज्य के नेताओं के साथ कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। इस बीच, कांग्रेस 2025 में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने का इरादा रखती है, जिसका लक्ष्य अपनी पैठ मजबूत करना है। दोनों प्रमुख पार्टियां महत्वपूर्ण राज्यों में जीत हासिल करने के लिए संसाधन जुटाने और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आम आदमी पार्टी (क्क), राष्ट्रीय जनता दल (ऋछ्व), जनता दल (यूनाइटेड) (छ्व) जैसी अन्य पार्टियाँ वर्ष 2025 के दौरान राजनीतिक स्पेक्ट्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

दिल्ली चुनाव

फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, 70 निर्वाचन क्षेत्रों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2020 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी (आप) का नेतृत्व अब मुख्यमंत्री आतिशी कर रही हैं। जहां आप का लक्ष्य सत्ता बरकरार रखना है, वहीं विपक्षी दल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस उसके एक दशक पुराने प्रभुत्व को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों ने,क्क पर शासन की विफलताओं का आरोप लगाया, जिसमें गंदे पानी की आपूर्ति, उच्च बिजली बिल, राशन कार्ड में देरी और पेंशन वितरण में चूक जैसे मुद्दे शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी, 2025 को समाप्त होने के साथ,

चुनाव दिल्ली के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच एक भयंकर लड़ाई का वादा करता है। दिल्ली में

दिल्ली में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी से भी कांग्रेस की बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ अन्य दल भी अपनी उम्मीदवार दिल्ली में उतार सकते हैं। दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो जदयू ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को भी एक या दो सीट दिल्ली में लड़ने के लिए दिया जा सकता है। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां के साथ के साथ सीटें भाजपा की झोली में गई थी।

बिहार चुनाव

अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025, 243 निर्वाचन क्षेत्रों में एक उच्च दांव वाली लड़ाई का वादा करते हैं। 2020 के चुनावों के बाद, नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेतृत्व किया, लेकिन अगस्त 2022 तक, वह राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए, केवल जनवरी 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में लौट आए। इस राजनीतिक पुनर्गठन ने कुमार को केंद्रबिंदु बना दिया है। भाजपा और सहयोगी दल उनकी घटती लोकप्रियता की आलोचना के बावजूद उनके नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं। अब जन सुराज पार्टी का नेतृत्व कर रहे प्रशांत किशोर ने जदयू के खराब प्रदर्शन की भविष्यवाणी की है और कहा है कि अगर वह 20 से अधिक सीटें हासिल करती है तो वह संन्यास ले लेंगे। राजद, कांग्रेस और वामपंथियों वाला इंडिया ब्लॉक आंतरिक दरारों और दलबदल से जूझ रहा है, जिससे वर्तमान में इसकी स्थिति और कमजोर हो गई है। हालांकि इससे एनडीए को प्री-पेड बिजली मीटर और जहरीली शराब त्रासदी जैसे शासन संबंधी मुद्दों पर जनता के असंतोष से राहत मिली है।

नए साल पर कबीर पंथ का संत समागम मेला

शोभायात्रा में संस्कृति की बिखरी छटा

बेमेतरा। जिले के लोलेसरा में चार दिवसीय संत समागम मेला का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर कबीर पंथ के श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा निकाली। इसमें लाखों की तादाद में प्रदेश भर के लोग शामिल हुए। शोभायात्रा के दौरान सिमगा से लेकर लोलेसरा तक लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं, संत समागम के समापन समारोह में 3 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल होंगे।

सिमगा से लेकर लोलेसरा के बीच शोभायात्रा में छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा की छटा भी दिखाई दी। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शोभायात्रा रात 8:00 बजे संत समागम मेला स्थल लोलेसरा पहुंची। जहां कबीर पंथ के गुरु डॉ भानु प्रताप नाम साहब और नवोदय वंषाचार्य उदित मुनीराम साहब के अभिनंदन में 42 हजार दीप प्रज्वलित किए गए।

बेमेतरा शहर के सिग्नल चौक में प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने कबीर पंथ के गुरु डॉ भानु प्रताप नाम साहब और नवोदय वंषाचार्य उदित मुनि नाम साहब का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बेमेतरा के पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल किसान नेता योगेश तिवारी भी मौजूद थे।

विधायक दीपेश साहू ने कहा दामाखेड़ा के बाद पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मेला बेमेतरा जिला के लोलेसरा में लगता है। संत समागम मेला के शोभायात्रा में सिमगा से लेकर लोलेसरा तक भीड़ उमड़ी रही। सभी ने गुरुओं का सम्मान किया है।

मेला स्थल में भोजन और ठहरने के इंतेजाम = कबीर पंथ के संत समागम मेला में देश के कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जिनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया गया है। यहां लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने एवं भोजन करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए विशाल डोम बनाया गया है, जिसमें सैंकड़ों की तादात में व्यवस्थापक रखे गए हैं, जो आगंतुकों के रहने और भोजन की व्यवस्था को संभाले हुए हैं।

दामाखेड़ा से निकली शोभायात्रा में हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। वहीं, बाइक रैली भी निकाला गया। शोभायात्र में भीड़ को लेकर सड़क डायवर्ट किया गया। भारी वाहनों को नगर प्रवेश नहीं दिया गया, उन वाहनों को बायपास से भेजा गया। इस कार्यक्रम का समापन के दौरान 3 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आगमन प्रस्तावित है। इसलिए मेला स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर एसपी रामकृष्ण साहू के निर्देश पर महिला सुरक्षा केंद्र और सैकड़ों जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।

जवानों ने 10 आईईडी बरामद कर किया डिफ्यूज

बीजापुर। बीजापुर में सुरक्षाबलों ने नए साल के पहले दिन नक्सलियों के मंसूबे को विफल कर दिया है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने सीरीज में लगाये गये आईईडी को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बासागुड़ा थाना व सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी आरओपी ड्यूटी पर निकली थी। इस दौरान तिम्मापुर दुर्गा मंदिर गौठान के पास पगडंडी रास्ते पर नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने बियर बॉटल में आठ नग आईईडी को सीरीज में प्लांट कर रखा था।

जिसे बीडी टीम ने बरामद कर उसे वही नष्ट कर दिया। वही तर्रेम थाना क्षेत्र में कोबरा की टीम ने कोंडापल्ली व छुटवाई के बीच बंदलएलका नाला के पास नक्सलियों द्वारा प्लांट किये गए 3-3 किलो के 2 आईईडी को बरामद कर उसे भी वही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। जवानों की सतर्कता व सूझबूझ से नक्सलियों के मंसूबे विफल हो गए।

साल के आखिरी दिन ताबड़तोड़ एक्शन

अवैध लकड़ी परिवहन करते आठ ट्रैक्टर जब्त

बालोद। साल के जाते-जाते बालोद वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ ट्रैक्टर लकड़ी सहित जब्त की है। वन मंडल अधिकारी बीएस सरोटे के निर्देशन में उप वन मंडल अधिकारी ने यह पूरी कार्रवाई की है। वनमंडलाधिकारी बीएस सरोटे ने बताया कि वन विभाग के अमले द्वारा रात्रिगश्त के दौरान बालोद-लोहारा मुख्य मार्ग पर पाररास से जुंगेरा के बीच चार ट्रैक्टर, बघमरा-बालोद मार्ग रेलवे फाटक के पास एक ट्रैक्टर, वनोपज जांच नाका तालगांव के समीप एक ट्रैक्टर समेत ग्राम चैरेल के पास दो ट्रैक्टर को अवैध काष्ठ परिवहन किये जाने के कारण जब्त किया है।

उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सभी वाहनमय काष्ठ को शासकीय काष्ठागार में रखा गया है। जब्त ट्रैक्टरों में कसही, साजा, प्रतिबंधित प्रजाति के अर्जुन वृक्ष तथा अन्य मिश्रित प्रजाति लट्ठा 12 घनमीटर तथा अन्य मिश्रित प्रजाति के छह जलाऊ चट्टा लदा पाया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टरों में जब्त काष्ठ के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर छत्तीसगढ़ वनोपज परिवहन अधिनियम 2001 के नियम तीन के तहत कार्रवाई की जा रही है।

आपको बता दें कि बालोद सहित आसपास के आरा मिल में प्रतिबंधित लकड़ियां खपाई जाती है और यहां पर बालोद में आने के लिए बायपास में बने एक धर्म कांटा में इसका माप किया जाता है। जिसके बाद ये आरा मिल को लेकर काम करते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा घटिया, बरही आदि क्षेत्रों में लकड़ी की कटाई की जा रही है। वहीं लोहारा पलारी ये क्षेत्र में लकड़ी कटाई से अछूते नहीं है। मामले में लगातार कार्रवाई करने की बात वन विभाग द्वारा कही जा रही है।

कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का स्वागत, अलाव बना सहारा

जीपीएम में ठंडी हवा ने कंपकंपाया

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मैकल पर्वत श्रंखला और अमरकंटक की तराई में बसे पेंड्रा गौरेला मरवाही इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल के पहले दिन घने कोहरे से पूरा क्षेत्र कोहरे की चादर में लपटा नजर आया। मौसम साफ होते ही ठंड का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वहीं उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते भी दिन के वक्त भी लोग गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं।

मौसम खुलते ही तापमान नीचे की ओर लुढका और यहां न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ओस की बूंदे भी जमने लगी है। तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे है।

नये साल के पहले दिन पेंड्रा गौरेला मरवाही इलाके में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। उत्तर भारत में हो रही लगातार बर्फबारी का असर इस इलाके में भी देखने को मिल रहा है। इलाके का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां पर लगातार तापमान में गिरावट के साथ दिन के समय भी ठंडी-ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग दिन के समय भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं।

हालांकि दिन के वक्त धूप निकलने की वजह से ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। हालांकि, ठंड की वजह से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मैकल पर्वत श्रंखला और अमरकंटक की तराई में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में ओस की बूंदे भी जमने लगी है। तो ठंड से बचने के लिए लोग चाय की चुस्की का सहारा भी ले रहे हैं। चाय की गर्म-गर्म चुस्कियां लेते लोग सुबह से ही ठेलो में नजर आने लग जाते हैं।

हालांकि अब तक चौक चौराहों में प्रशासन के द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के बाद उत्तरी हवाओं के असर के चलते ही इलाका कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है।

जांगला आत्मानंद स्कूल में नदारद मिले 13 शिक्षक

डीईओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

बीजापुर। जिले के जांगला के आत्मानंद हिंदी-अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नदारद 13 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब-तलब किया गया है। डीईओ एलएल धनेलिया ने बताया कि एक साथ संस्था से इतने सारे शिक्षकों का नदारद रहना उनके कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले शिक्षक व अन्य कर्मियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन कटौती की कार्रवाही की जाएगी। विदित हे कि 24 दिसंबर को भी जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पोटाकेबिन चिन्नाकोडेपाल व पोटाकेबिन दुगाईगुडा के अधीक्षकों पर दो वेतन वर्द्धि रोकने की कार्रवाही करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। वहीं अन्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

जिला शिक्षा अधिकारी एलएल धनेलिया ने आज मंगलवार को जांगला स्थित आत्मानंद हिंदी-अंग्रेजी माध्यम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। डीईओ के निरीक्षण पर वहां से सहायक शिक्षक केजी तरुण, सहायक शिक्षक कुमारी साक्षी कुमार, सहायक शिक्षक जगदीश पटेल, पीटीआई एनोस दास, व्याख्याता प्रवीण लकड़ा, व्याख्याता रोशनलाल कोसले, सहायक शिक्षक रिंकू कोसले, व्याख्याता कुमारी माधुरी शार्दूल, व्याख्याता सूर्यकांत यादव, व्याख्याता एलबी ममता उपाध्याय, व्याख्याता एलबी मीना साहू, सहायक ग्रेड-2 कृष्णा राव पोंदी व सहायक ग्रेड-3 संदीप मिंज अनुपस्थित पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी 13 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब-तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी।

कांकेर सांसद का फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते विडियो हुआ वायरल

कांकेर। जिले के कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बताया जा है कि रावघाट इलाके के ट्रैक्टर व जेसीबी मालिकों ने ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं करने की शिकायत की थी। जिस पर सांसद जेसीबी मालिक के फोन से ठेकेदार से बात करने लगे। तभी अचानक सांसद बिफर गए और पब्लिक के सामने ही ठेकेदार को अपशब्द कहने लगे, इसका वीडियो अब शोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांकेर सांसद भोजराज नाग ने कहा कि मुझे गाली दी, इसलिए मैने कहा मैं तेरा बाप बोल रहा हूं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

पूरे मामले में ट्रेक्टर और जेसीबी मालिक ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिसे लेकर भैंसगांव में रावघाट परियोजना को लेकर एक बैठक रखी गई थी, इसमें सांसद भोजराज नाग पहुंचे थे। बैठक के पीडितों के द्वारा अपनी समस्या बताने के दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए मोबाइल से ठेकेदार की बात सांसद भोजराज नाग से करवाई। वीडियो में सांसद कह रहे हैं कि कौन बौल रहे हो? ग्रामीणों का पैसा क्यों नही दे रहे हो? इस पर फोन पर दूसरी ओर मौजूद ठेकेदार अजय साहू भड़क गया और कहने लगा कौन बोल रहा है बे। इसके बाद अपशब्द कहते हुए बोला कि तुम कौन होते हो मुझे पैसा देने के लिए बोलने वाले। मामले में रावघाट पुलिस आरोपी ठेकेदार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर इसकी जांच कर रही है।

रावघाट थाना प्रभारी सोमेंद्र बघेल ने बताया कि रावघाट पुलिस ने सांसद के निर्देश और ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। ठेकेदार अजय साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि ठेकेदार ने जमानत याचिका दायर कर न्यायालय से जमानत ले ली है, उसे रिहा कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बाघिन की मौजूदगी से बढ़ी वन अमले की चिंता

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। मरवाही वनमंडल के जंगल में बीते कुछ दिनों से बाघिन की मौजूदगी ने वन विभाग की चुनौती बढ़ा दी है। हालांकि, जिले के पर्यटन स्थलों की ओर उसकी आमद नहीं होने से बाघिन को ट्रेक कर रहे अमले के लिए थोड़ी राहत भरी बात है। वाइल्ड लाइफ की टीम और वन कर्मी बाघिन की गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। बाघिन के गले में कॉलर आईडी लगे होने की वजह से उसके पल-पल की गतिविधियों का पता भी चल रहा है। यही वजह है कि वाइल्ड लाइफ, एटीआर और वन विभाग की टीम समय रहते लोगों को सतर्क करने में सक्षम है। खोडरी रेंज में मौजूद बाघिन ने गाय और बछड़े का शिकार किया है। डीएफओ रौनक़ गोयल मरवाही वनमंडल बाघ का विचरण मरवाही वन क्षेत्र में है, और निकटतम राजस्व ग्रामों जैसे उम्रखोई, करिआम इत्यादि में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। पर्यटन स्थल लक्ष्मणधारा और जोझा के लिए वन विभाग का कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुआ है। उधर विचरण भविष्य में रहेगा तो अलर्ट किया जाएगा।

चावल और मुर्गे को लेकर दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद

बिलासापुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर का जश्न मना रहे एक राजमिस्त्री ने अपने चौकीदार दोस्त की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आज मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया और आरोपी राजमिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान काठा कोनी के भिलौनी गांव के निवासी सोनू उर्फ सुरेश सूर्यवंशी के रूप में हुई है। मृतक सुरेश सूर्यवंशी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रिंग रोड-2 में निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी का काम करता था। जबकि आरोपी राजमिस्त्री अजीत टोप्पो (सारंगढ़ निवासी) भी उसी निर्माणाधीन मकान में काम करता था और वहीं निवासरत था। दोनों ने मिलकर साल 2024 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को शराब के साथ मुर्गा पार्टी करने का प्लान बनाया था। दोनों आपस में पैसे मिलाकर शराब खरीदी। राजमिस्त्री अजीत ने मुर्गा लाया, फिर सब्जी बनाकर दोनों आपस में शराब पार्टी की।

सरोधादादर में मना नया साल सैलानियों का लगा जमावड़ा

कवर्धा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इस खास मौके को और भी खास बनाने दूर-दूर से लोग अपने परिवार ,दोस्तों के साथ कबीरधाम जिले की सबसे उंचा स्थान सरोधादादर में एंजॉय करने पहुंचे। पूरे जोश के साथ नए वर्ष का स्वागत किया। रातभर लोग झूमते नजर आए। जिससे सरोधादादर में रौनक बनी हुई है। पर्यटक नए साल की खुशियां चिल्फी घाटी और सरोधादादर की खुबसूरत वादियों के बीच मनाए और खूब एंजॉय किया। प्राकृतिक धरोहरों से परिपूर्ण है कवर्धा = सरोधादादर कबीरधाम जिले के सबसे ऊंची मैकल पर्वत श्रंखला की तट पर स्थित है। यहां से ऊंची-ऊंची पहाड़ भी बौनी नजर आती है।चिल्फी घाटी की टेढ़ी-मेढ़ी रास्तों से होकर गुजरता रोड़ और शिमला का एहसास कराने वाला ठंड लोगों का दिल मोह लेता है।सूर्य उदय का नजारा पर्यटकों को नई ऊर्जा देता है। इस खूबसूरत नजारे का आंनद लेने हर साल पर्यटक नया साल मनाने यहां आते हैं।खूबसूरत वादियों का आंनद लेते हैं। कबीरधाम जिले में अनेक पर्यटन स्थल प्राचीन मंदिर है।

जंगली सुअर को मारने के लिए बिछाया करंट तार

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कचंदा में जंगली सुआर मारने की बिछाई करंट की चपेट में आने से एक नाबालिक लड़के की मौत हुई है। वहीं दूसरा नाबालिग लड़का घायल हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना शिवरीनारायण थाना क्षेत्र की है। शिवरीनारायण पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2024 को ग्राम कचंदा के जंगल में अज्ञात लोगों के द्वारा तालाब के किनारे लगे 11 केवी के ट्रांसफार्मर से जंगली सुआर को मारने के लिए जाल बिछाया गया था। जिसमें गांव के तीन नाबालिक लड़के शौच के लिए पहुंचे हुए थे अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दिया जिसमें यशु यादव के घुटना जल है वह हरीश सिंह चौहान की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं तीसरा नाबालिक लड़का बच गया। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। बुधवार की सुबह पुलिस की टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वही शिवरीनारायण थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे 3 युवक हादसे का शिकार

कोरबा। कोरबा में पहली जनवरी की देर रात नशा और तेज रफ्तार के कारण तीन युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में कुसमुंडा निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, नए साल 2025 के आगमन की खुशी में पार्टी मना रहे दो से तीन युवक एक मारुति बलेनो कार में सवार होकर तेज रफ्तार से चला रहे थे। घटना मानिकपुर पुलिस चौकी अंतर्गत मुड़ापार-सुभाष ब्लाक कालोनी मार्ग से गुजरते वक्त मोड़ के पास सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभे से जा टकराई। कार की रफ्तार का अंदाजा घटनास्थल के दृश्य से लगाया जा सकता है जहां कार की ठोकर से आसपास की दुकानों के छप्पर उड़ गए और खम्भा भी टूट गया। इतना ही नहीं कार पलट गई। कार में सवार कुसमुंडा निवासी अनुभव मसीह की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक आदर्श नगर कुसमुंडा निवासी एसईसीएल कर्मी बताया जा रहा है। कार में सवार दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गन्ना किसानों के अध्ययन दल को महाराष्ट्र के लिए रवाना किया

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज गन्ना किसानों के एक अध्ययन दल को महाराष्ट्र के लिए रवाना किया। इस दल में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के कार्यक्षेत्र के शतक से अधिक किसान शामिल हैं। यह यात्रा किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती की उन्नत तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।

इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने संबोधन में किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई जानकारियों और तकनीकों के महत्व को बताया। उनके साथ प्राधिकृत अधिकारी और कलेक्टर गोपाल वर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि यह यात्रा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वे गन्ने की खेती में नवीनतम अनुसंधान और तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे।

यह अध्ययन दल 1 जनवरी की सुबह कवर्धा से प्रस्थान कर महाराष्ट्र के पुणे स्थित वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट पहुंचेगा, जहां किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में गन्ने की आधुनिक किस्मों, अधिक उत्पादन और उच्च रिकवरी प्राप्त करने की तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद किसान महाराष्ट्र के पड़ेगांव गन्ना रिसर्च सेंटर और बारामती कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे, जहां उन्हें गन्ने की खेती में अनुसंधान आधारित नवीनतम तकनीकों की जानकारी मिलेगी। यात्रा के दौरान किसान पंढरपुर स्थित शक्कर कारखाने का भी भ्रमण करेंगे और शक्कर उत्पादन की प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे। इसके बाद, सतारा में किसानों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गन्ने की खेती से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को गन्ने की खेती में आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे अपनी फसल में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जिले में गन्ना उत्पादन को एक नई दिशा भी मिलेगी। इस अवसर पर दोनों शक्कर कारखानों के प्रबंधसंचालक, कैलाश चंद्रवंशी, भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने शा. पॉलिटेक्निक संस्था संचालित

- 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से पीपीटी की तैयारी करने अनुरोध

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से मरवाही में शासकीय पॉलिटेक्निक संस्था संचालित है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पॉलिटेक्निक संस्था का संचालन शासकीय हाईस्कूल लोहारी, मरवाही में किया जाएगा। संस्था के प्राचार्य ने बताया है कि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संस्था में प्रवेश लेने के लिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट (पीपीटी) की परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा मई-जून में आयोजित की जाती है। इसके लिए आवेदन फार्म अप्रैल माह में भरा जाता है। पीपीटी परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन फार्म निःशुल्क होता है। परीक्षा के रैंक के आधार पर काउंसलिंग के दौरान ब्रांच का चयन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। छात्रों को 10वीं की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करना होता है।

शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में युवाओं को व्यावहारिक और रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां कंप्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने पर छात्रों को रोजगार के लिए व्यावसायिक कौशल प्राप्त होता है और वे सीधे उद्योगों में नौकरी के लिए योग्य बनते हैं। इसके अलावा बीटेक के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक संस्थान में बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए मेरिट एवं प्रगति छात्रवृत्ति और सभी छात्रों के लिए पुस्तकालय तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी की सुविधा दी जाती है। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर +91-7000597263 और +91-8463866607 पर संपर्क किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

श्री रामचरित मानस प्रसंग पर प्रवचन के लिए रायपुर पहुंचे मैथिलीशरण भाईजी

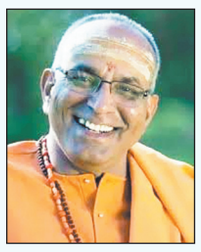

रायपुर। श्री रामचरित मानस प्रसंग पर गूढ़ व्याख्या के लिए श्री रामकिंकर विचार मिशन के मैथिलीशरण भाईजी 1 जनवरी को रायपुर पहुंचे और 3 जनवरी से उनका प्रवचन शाम से प्रारंभ होगा। यह जानकारी श्री रामकिंकर विचार मंच के पुरुषोत्तम सिंघानिया, डा. नवनीत जैन और भारत भूषण गुप्ता ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में दी। उन्होने बताया कि रामकिंकर विचार मिशन के और महाराजश्री रामकिंकर जी के परम शिष्य मैथिलीशरण भाईजी विगत अनेक वर्षों से रामचरित्र मानस के प्रसंगों की गूढ़ता का सरल और सामान्य भाषा में प्रवचन करते आ रहे है, जिसका रसास्वादन शहर तथा आसपास के अनेक ग्रामीणजन भी आकर करते है। इस बार भाईजी रामचरित्र मानस के गूढ़तम प्रसंगों में से एक मां श्री सीता जी के दिव्य स्वरूप अद्वैतरूपी शक्ति स्वरूपा के प्रसंग पर प्रवचन करेंगे। प्रवचन संध्या 7 से 8.30 बजे तक 3 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रतिदिन 7 बजे से महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय समता कालोनी में होगा। प्रवचन से पूर्व संध्या 6.30 से 7 बजे तक मिथिला एवं चित्रकूट से आए गायकों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति होगी। तत्पश्चात श्री रामचरित मानस के अमृतमय स्वरूप का श्रवण कर धन्यता को प्राप्त करेंगे।

विस अध्यक्ष ने किया छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कैलेंडर का विमोचन

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.

रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि इस कैलेंडर में सार्वजनिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश के साथ महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर भी दिया गया है। इस अवसर पर बी. पी. शर्मा, आर.के.रिछारिया, अभिषेक शर्मा, सत्येंद्र देवांगन, संतोष कुमार वर्मा, लिलेश्वर देवांगन उपस्थित थे।

2012 बैच के 8 आईएएस अफसरों को मिला पदोन्नति, एक को प्रोफॉर्मा पदोन्नति

रायपुर। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा देते हुए 2012 बैच के 8 अधिकारियों को संयुक्त सचिव से विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएस अधिकारी शिव अनंत तायल को प्रोफॉर्मा पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति किए गए अधिकारियों में रजत बसल - भा.प्र.से. (2012), रितेश कुमार अग्रवाल - भा.प्र.से. (2012), अभिजीत सिंह - भा.प्र.से. (2012), रणबीर शर्मा - भा.प्र.से. (2012), पुष्पेन्द्र कुमार - मीणा, भा.प्र.से. (2012), तारन प्रकाश सिन्हा - भा.प्र.से. (2012), इफ्फत आरा - भा.प्र.से. (2012), दिव्या उमेश मिश्रा - भा.प्र.से. (2012), पुष्पा साहू - भा.प्र.से. (2012) तथा संजय अग्रवाल - भा.प्र.से. (2012) शामिल है।

दो प्रधान प्राचार्य में एक बने डीईओ और एक सहायक संचालक

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने दो ई संवर्ग के प्रधान प्राचार्यों का तबादला करते हुए एक को डीईओ और एक को सहायक संचालक के पद पर पदस्थ किया। जारी आदेश के अनुसार भारती प्रधान को प्रभारी जिला शिक्षाधिकारी कोंडागांव और आदित्य चांडक को सहायक संचालक कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर में पदस्थ किया गया है।

सीएसईबी में 53 अधीक्षण अभियंता किए गए पदोन्नत

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने साल के अंतिम दिन 59 अधिकारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया है। कंपनी ने जूनियर इंजीनियर से सहायक अभियंता, सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता, और कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किए गए।

मुख्यमंत्री ने संत पवन दीवान की जयंती पर उन्हें नमन किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने

छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि और प्रसिद्ध कथावाचक संत पवन दीवान की 1 जनवरी को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने संत दीवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि संत पवन दीवान ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । उन्होंने कहा कि पवन दीवान जी की बातों में माटी की सोंधी महक थी, जिससे आम जनता सहज ही जुड़ जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीवान जी की यादें छत्तीसगढ़ के जनमानस में हमेशा बनी रहेंगी।

नवा रायपुर अटल नगर में एकीकृत उपनगर के विकास हेतु नियमों का सरलीकरण

नवा रायपुर में एकीकृत उपनगरों के विकास को मिलेगी गति और क्षेत्र में बसाहट को मिलेगा बढ़ावा - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगर के विकास को प्रोत्साहित करने के उ?देश्य से मौजूदा नियमों को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। यह कदम क्षेत्र में बसाहट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि इन आवश्यक सुविधाओं का विकास उपनगर के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सुधारों का मुख्य उ?देश्य नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को गति देना और क्षेत्र में बसाहट को बढ़ावा देना है। यह कदम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, और धार्मिक स्थलों के लिए आरक्षित क्षेत्र को न्यूनतम 5 प्रतिशत किया गया है, जो पहले अधिकतम 5 प्रतिशत था। इसके अलावा आवासीय गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए, पूर्व में निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को बदल कर अब न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे आमजन के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और लोगों को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) संबंधित प्रावधान को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिसूचना/नियमों के अनुरूप करते हुए संबंधित प्रावधानों में सुधार किया गया है, ताकि इन नियमों में एकरूपता लाई जा सके।

पीएम आवास योजना गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करें: शर्मा

रायपुर। कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा से विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज बुधवार को यहां के दौरे पर है। वे आज कवर्धा विधानसभा के विभिन्न गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे ग्राम तिवारी नवागांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। इसी गांव में पीएम आवास के हितग्राहियों से भी मुलाकात की व अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत घर का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने योजना के तहत बनाए जा रहें घर का निरीक्षण किया व लाभार्थियों से बातचीत कर अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इस बात पर जोर दिया कि हर लाभार्थी को समय पर, पूरी गुणवत्ता के साथ अपना आवास मिलना चाहिए, ताकि वे जल्द से जल्द अपना नया घर पा सकें।

गन्ना किसानों के दल को महाराष्ट्र रवाना किया

दौरे कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने गन्ना किसानों के एक दल के बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के गन्ना किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक से परिचित कराने महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। अध्ययन दल में शामिल किसान वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे पहुंचेंगे। यहां किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें गन्ने की आधुनिक किस्म, अधिक उत्पादन व उच्च रिकवरी प्राप्त करने के तकनीकी जानकारी दी जाएंगी। इसके बाद किसान पड़ेगांव गन्ना रिसर्च सेंटर, बारामती कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे।

कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अपमान को देखकर कोई भी सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लगातार दुर्गति हो रही है, लेकिन बजाय इससे सबक लेने के कांग्रेस के लोग आपसी सिर-फुटौव्वल में लगे हुए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा के संगठन महापर्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 60 लाख सदस्य बनाकर इतिहास रचा है और कांग्रेस की दुर्दशा का आलम यह है कि वहाँ कोई सदस्य बनने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं है।

शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के अभाव से जूझ रही कांग्रेस की राजनीतिक दरिद्रता का इससे अधिक परिचय और क्या होगा कि अब कांग्रेस नेतृत्व को पिछले चुनावों के और निष्कासित नेताओं से आवेदन मंगवाना पड़ा है! कांग्रेस के इसी राजनीतिक चरित्र के कारण एक तरफ जहाँ सम्मेलनों में बड़े नेताओं को कार्यकर्ता मुँह पर खूब खरी-खोटी सुनाने में नहीं हिचक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अपमान को देखकर कोई भी कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा की ऐतिहासिक सदस्य संख्या भाजपा के प्रति अटूट जन-विश्वास का प्रमाण पत्र है। भाजपा विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसकी तमाम व्यवस्थाएँ अपने दलीय संविधान के अनुरूप संचालित होती हैं, जबकि एक परिवार की चरण वंदना ही कांग्रेसियों की कुल जमा राजनीतिक पूंजी है और अपराध और भ्रष्टाचार कांग्रेस सदस्यता की योग्यता का एकमात्र मापदंड रह गया है। अपने इसी राजनीतिक चरित्र और आचरण के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है।

यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी 200 करोड़ रूपए की स्वीकृति

■ यूनिटी मॉल से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

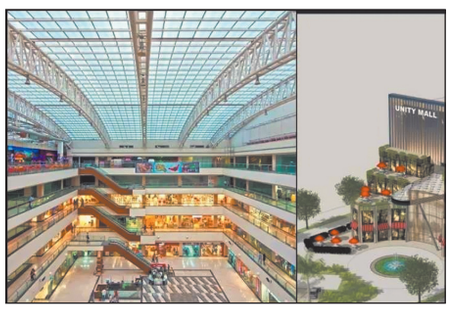

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं।

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।

मंदिर का दर्शन कर नववर्ष का आगाज

रायपुर। साल 2025 की शुरुआत आज यानी बुधवार से हो चुकी है। साल के पहले दिन लोग या तो पिकनिक पार्टी और पर्यटन के लिए बाहर निकलते हैं। वहीं कई लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन से पहले दिन की शुरूआत करते हैं। भक्तों की चाहत होती है कि भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करें। यही सोचकर महिला पुरुष बच्चे सभी मंदिर में भगवान के सामने माथा टेककर अपनी मन्नत और मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं।

रायपुर के राम मंदिर में सुबह से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने भक्तों को मंदिर में भगवान के दर्शन आसानी से हो, इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की है। राजधानी रायपुर के राम मंदिर में ईटीवी भारत ने भक्तों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि साल का पहला दिन होने के कारण लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है।

श्रद्धालु रत्नेश गुप्ता ने कहा पहले दिन की शुरुआत अगर भगवान के साथ हो तो आगे जीवन में सब अच्छा होता है। हमें एक मानसिक सपोर्ट मिलता है कि भगवान हमारे साथ हैं।

श्रद्धालु करुणा गुप्ता ने कहा हर कोई चाहता है कि पहले दिन की शुरूआत भगवान के दर्शन, पूजा पाठ और आराधना से हो, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आ सके। हम पूरे परिवार के साथ साल के पहले दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं। इस साल बहुत भीड़ दिख रही है। लोगों में आस्था बढ़ी है।

श्रद्धालु शैलेंद्र रिछारिया ने कहा नए साल को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। भगवान से मनोरथ पूरा करने की मंगलकामना करते हैं। श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि नए साल पर लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। सभी चाहते हैं कि नया साल नई खुशियां, नया उत्साह और नई उमंग लेकर आते हैं। श्रद्धालु कल्पना सिंह ने कहा मैं कामना करती हूं कि नववर्ष सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और भगवान करे कि सभी की मनोकामना पूरी हो। लोग बहुत उत्साहित हैं। बहुत भीड़ है। लोग चाहते हैं कि नया साल भगवान की पूजा अर्चना के साथ शुरू हो ताकि पूरे साल वे उत्साहित रहें।

राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए न सिर्फ रायपुर बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वह पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि की मनोकामना लेकर भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं।

श्रद्धालु दीपचंद देवांगन ने कहा हम राजनांदगांव से आए हैं। हम चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहे। यह मनोकामना लेकर भगवान का दर्शन करने आए हैं। भगवान राम के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मंदिर में व्यवस्था भी अच्छी की गई है।

लोगों का कहना है कि बीता साल 2024 चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन हमारा आने वाला साल उज्ज्वल और काफी अच्छा हो यही कामना लेकर लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु दीपिका ने कहा पुराना साल जैसा भी बीता हो, नया साल अच्छा गुजरना चाहिए। भगवान के दर्शन कर मंगलकामना की है। भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। नए साल का पहला दिन होने की वजह से राजधानी के सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।

बिकने और बेचने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस का पूरा साल निकल गया : श्रीवास्तव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि बिकना और बेचना कांग्रेस का मूल राजनीतिक चरित्र रहा है। बागियों और निष्कासित कांग्रेस नेताओं की वापसी को लेकर कांग्रेस में मचे बवाल ने कांग्रेस के इसी राजनीतिक चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बिकने और बेचने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस का यह पूरा साल निकल गया है।

श्रीवास्तव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा टिकटों की खरीद-फरोख्त से इंकार पर पलटवार करते हुए कहा कि बैज अगर कांग्रेस का पूरा इतिहास खंगाल लें तो उनकी यह खुशफहमी काफूर होते देर नहीं लगेगी। कांग्रेस ने तो अपना राजनीतिक चरित्र, जमीर तक बेच डाला है, भ्रष्टाचार करके लूट मचाने और देश व प्रदेश के मान-सम्मान बेचने में कांग्रेस को जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई, वह कांग्रेस आज टिकटों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर लिजलिजी दलीलें दे रही है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बैज अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में टिकटें बेचने से इंकार करके यह तो स्वीकार कर रह हैं कि उनके पहले कांग्रेस में यह सब होता रहा है। अगर बैज के कार्यकाल में टिकटों की खरीद-फरोख्त नहीं हुई थी, तो फिर 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस में टिकटें बेचने के सनसनीखेज आरोप तथ्यों के साथ कौन लगा रहा था? अगर टिकटें नहीं बिकी थीं तो फिर कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश प्रभारी शैलजा पर कांग्रेस के आलाकमान ने गाज क्यों गिराई थी? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार सरकारी खजाने को लूटने में लगी रही, उस पार्टी तक के खजाने में डाका डाले जाने के आरोप आज भी प्रदेश में गूंज रहे हैं, और बैज अपना दामन बचाने में लगे हैं।

बीएड सहायक शिक्षकों का भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों के निलंबन का आदेश देर रात छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया था। जिसके बाद सहायक शिक्षक ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया।इस दौरान 2 हजार से ज्यादा की संख्या में सहायक शिक्षक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश का कोई भी नेता मौजूद नहीं था।धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा लेकिन शिक्षक अपने रोजगार को लेकर अड़े हुए हैं।

मीडिया से बात करते हुए सहायक शिक्षकों ने कहा कि सरकार की मंशा मजबूत नहीं है इसीलिए इस बात को लगातार टाला जा रहा है। शिक्षकों ने कहा कि राजनीतिक रूप से अगर चीजों को करना होता है तो सरकार निर्देश जल्दी जारी कर देती है। महतारी बंदन योजना सरकार के लाभ की योजना है जिसमें इनको वोट का फायदा मिलना है तो 15 दिन में पैसे बांट दिए गए। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक बुनियाद मजबूत होनी है वैसे शिक्षकों को सड़क पर लाकर सरकार ने छोड़ दिया है। शिक्षकों ने इसे लेकर के शिक्षा मंत्री विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से भी मुलाकात की थी। लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकला

जिसके बाद बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में गुहार लगाई।इस दौरान सहायक शिक्षकों ने कार्यालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया। सहायक शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए।भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे इन सहायक शिक्षकों कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।इसके पहले अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों ने मुंडन कराया था। इसके बाद जल समाधि लेकर प्रदर्शन किया।

बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे सहायक शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी खतरे में हैं। सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। साथ ही इस मामले में पार्टी से भी हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिससे उनकी नौकरी बचाई जा सके। सहायक शिक्षकों की मांग है कि नौकरी को स्थाई करने की प्रक्रिया तेज की जाए। शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। भारी संख्या में जुटे सहायक शिक्षकों ने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय पहुंचकर अपनी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है।बीजेपी कार्यालय में मौजूद बीजेपी नेताओं ने सहायक शिक्षकों से बात की। उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को दो सप्ताह के अंदर डीएड डिग्रीधारक को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं, बीएड डिग्रीधारक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की बात कही थी। जिससे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई।बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त हिदायत दी थी कि अगर 15 दिनों के भीतर भर्ती का प्रोसेस पूरा नहीं किया गया तो अदालत कड़ी कार्रवाई करेगा।

2855 बीएड सहायक शिक्षकों को जारी हुआ सेवा समाप्ति का नोटिस

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिवस के भीतर नियुक्ता अधिकारी के समक्ष अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही हटाए गए सहायक शिक्षको के स्थान पर व्यापमं द्वारा जारी मेरिट सूची एवं आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए डीएड अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने डीईड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों के लिए सहायक शिक्षक की नौकरी पर संकट आ गया था। 19 दिसंबर से बीएड सहायक शिक्षक नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब लोक शिक्षण संचालनालय ने इन सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

नयी उम्मीदों और नये संकल्पों का वर्ष

क्षमा शर्मा

कुछ दशक पहले तक नया साल आने की धूमधाम इतनी सुनाई नहीं देती थी। तब कहा जाता था कि यह नया साल भारतीय नहीं है। फिर बीती सदी के 90 के दशक में मीडिया का फैलाव हुआ। टीवी चैनल घर-घर जा पहुंचे। छोटे शहर, गांव सब जगह दूरदर्शन के दर्शक बने और नया साल भी शुरू हो गया। आज भी कुछ लोग पश्चिमी संस्कृति कहकर इसके विरोध में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मगर कौन सुनता है! फिर से नया साल आ गया है। कई लोगों की पोस्ट फेसबुक पर देखती हूं, तो वे नवंबर-दिसंबर से ही कहने लगते हैं कि आने वाले साल में टाइम टेबल बनाकर काम करेंगे। ये बीते वर्ष से लिये गये सबक होंगे, क्योंकि इस साल कई महत्वपूर्ण काम छूट गये। नये साल में और क्या-क्या हो सकता है, इसके बारे में कई लोग बता रहे हैं कि वे नौकरी बदलने की सोच रहे हैं। इस साल इस बारे में वे गंभीरता से प्रयास करेंगे। कुछ का कहना है कि वे पिछले साल यूरोप की सैर करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाये, तो इस साल अपने सपने पूरे करेंगे। कुछ लोग अपने गांव में कुछ महीना बिताकर अपने बचपन को लौटा लाना चाहते हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन गांवों में रहकर वे महानगरों में फैले प्रदूषण से बचेंगे, हरियाली के साथ वक्त बितायेंगे, गन्ने और गुड़ का आनंद लेंगे। बहुत-से युवाओं को उम्मीद है कि इस साल वे अपने माता-पिता को मना लेंगे और जाति-धर्म से परे अपने प्यार को पा लेंगे। इस नये साल में सबसे पहले बच्चों, युवाओं को परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है, इसकी तैयारी तो वे बीते साल से ही कर रहे होंगे। अब परीक्षा बिल्कुल सिर पर दिखायी दे रही होगी। विशेषज्ञों की राय में छात्र बिल्कुल भी तनाव न लें। सफलता मिलने में तनाव बेहद घातक है। छात्र पढ़ने में तो समय बिताएं ही, कुछ समय मनोरंजन और हिलने-मिलने को भी दें। यदि संयुक्त परिवार में रहते हैं, दादा-दादी साथ हैं, तो उनके साथ वक्त बितायें। उनसे बातचीत तनाव दूर करती है। कुछ साल पहले परीक्षा के दिनों में बच्चों में होने वाले तनाव पर तमिलनाडु में एक अध्ययन किया गया था। उसमें पता चला था कि एकल परिवारों में रहने वाले बच्चों की तुलना में संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चों में परीक्षा के दिनों में तनाव और चिंता कम होती हैं। एकल परिवार में रहने वाले बच्चे भी अपने नाते-रिश्तेदारों और मित्रों से बातचीत कर सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में बच्चों और युवाओं की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। वैसे भी इस साल तो प्रयागराज में बारह साल में एक बार आने वाला महाकुंभ भी लग रहा है। असंख्य लोग वहां जायेंगे और संगम में स्नान और पूजा-आराधना की अपनी इच्छा पूरी करेंगे। नये साल में हम जो भी संकल्प लें, उनमें एक संकल्प टाइम मैनेजमेंट का तो होना ही चाहिए। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, यह तो हम सब जानते ही हैं। टाइम मैनेजमेंट का यह मूल मंत्र है। पिछला साल डिजिटल अरेस्ट और करोड़ों की धोखाधड़ी की खबरों से गूंजता रहा। कितने युवा, बुजुर्ग, बच्चे, साइबर ठगी के शिकार हुए। मशहूर हिंदी कवि नरेश सक्सेना भी इसके जाल में फंसने से बाल-बाल बचे। इनसे बचने के उपायों के रूप में जांच एजेंसियां कहती हैं कि अपने बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां तक कि व्हाटसएप पर भी जानकारी साझा न करें। हर एक को अपना मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, ई-मेल आइडी आदि नहीं देने चाहिए। और अपनी परेशानियां भी अपने परिवार वालों या निकट मित्रों से ही साझा करनी चाहिए। महान कवि रहीम के इस दोहे को याद रखा जा सकता है- 'रहिमन निज मन की बिथा मन ही राखौ गोय, सुन इठिलैहैं लोग सब बांटि न लेहैं कोय'। यानी, यदि आप अपनी परेशानियां सबको बताने लगे, तो मजाक उड़ाने वाले तो सब मिलेंगे, परेशानी बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। यूं इस साल के बारे में बहुत-सी अच्छी बातें सोची जा सकती हैं। काश, कि दुनिया से हथियारों के जखीरे खत्म हो जायें, सब शांति से रह सकें। रूस, यूक्रेन, इस्राइल, फिलीस्तीन का युद्ध समाप्त हो। दुनिया से भूख, गरीबी और आतंकवाद का अंत हो। स्वास्थ्य उद्योग व्यापारिक हितों के मुकाबले, आम लोगों के हित में काम करे। सभी देश यह प्रतिज्ञा करें कि किसी के भड़कावे में आकर वे अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ेंगे।

मोदी सरकार की परीक्षा का साल होगा 2025

जयसिंह रावत

नए साल 2025 में मोदी सरकार के सामने राजनीतिक परिदृश्य और अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। 'एक देश, एक चुनाव' जैसी महत्वाकांक्षी पहल के लिए समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा, खासकर जब इस मुद्दे पर विभिन्न दलों की राय विभाजित है। इसके साथ ही आंबेडकर विचारधारा से जुड़े सामाजिक मुद्दों और अडानी प्रकरण पर विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करते हुए सरकार को अपनी नीतियों और छवि को मजबूत बनाए रखना होगा।

ऐसे में यह वर्ष सरकार के लिए न केवल राजनीतिक कौशल की परीक्षा का होगा, बल्कि जनता के भरोसे को कायम रखने की भी। वक्फ बिल अभी पास नहीं हुआ है और उत्तराखण्ड जैसे राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून बन भी चुका है। 2025 का भारत, एक नई राजनीतिक दिशा और संभावनाओं के साथ, गहराते सामाजिक-राजनीतिक विभाजन और असंतोष के दौर से भी गुजर सकता है।

पक्ष विपक्ष के बीच प्रतिद्वन्दिता दुश्मनी का रूप लेती जा रही है। मोदी सरकार, जो 2024 में चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी है, को न केवल अपने एजेंडे को लागू करने की चुनौती होगी, बल्कि विपक्ष और जनता की अपेक्षाओं के बीच संतुलन भी साधना होगा।

एक देश, एक चुनाव : कहना आसान और करना कठिन- मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव का बिल संसद में पेश तो कर दिया, लेकिन एक साथ चुनाव कराना इतना आसान नही है। यह विचार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा है। इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। मोदी सरकार के लिए इसे पास करना कई कारणों से चुनौतीपूर्ण होगा। इसे लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, और 356 में संशोधन करना पड़ेगा।

सरकार की इस पहल को लेकर कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इस पर अदालतों में याचिकाएं दायर हो सकती हैं। न्यायपालिका का दृष्टिकोण भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगा। इसके लिये संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक है। जबकि विपक्षी दल इसे सत्ता के केंद्रीकरण और संघवाद के लिए खतरा मानते हैं। क्षेत्रीय दल, जिनकी राजनीति राज्य स्तर पर केंद्रित है, इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप मान सकते हैं।

इसलिए एनडीए घटकों का समर्थन जुटाना ही चुनौतीपूर्ण होगा। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि राज्यों की विधायिकाओं का कार्यकाल छोटा या बड़ा करना। यही नहीं पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के लिए इसे संभालना कठिन हो सकता है।

वक्फ बोर्ड के बिल को पास कराना भी एक चुनौती- वर्तमान में, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यक विरोधी नीति बताकर मुद्दा बना रहा है। राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत है, जिससे इस विधेयक को पारित कराना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है।

हालांकि, विधेयक की संवेदनशीलता और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को देखते हुए, इसे पारित कराने में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। क्योंकि अपने मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुये सरकार को टिकाये रखने वाले चन्द्र बाबू नायडू और नितीश कुमार इस बिल को समर्थन देने से मुकर सकते हैं। वैसे भी अगर यह बिल पास कराना इतना आसान होता तो सरकार इसे जेपीसी को क्यों भेजती?

संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक जल्द ही होने की संभावना है, जो विधेयक की समीक्षा करेगी और आवश्यक संशोधनों पर विचार करेगी। इस प्रक्रिया के बाद, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित कराना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसके लिए राजनीतिक सहमति और समर्थन जुटाना आवश्यक होगा।

अम्बेडकर को लेकर विवाद से भी निपटना होगा- संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. भीमराव आंबेडकर पर की गई टिप्पणी से उत्पन्न विवाद ने भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। विपक्ष इस बयान को आंबेडकर का अपमान बताते हुए गृह मंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिये दिल्ली में डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान और उनके विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

जबकि, कांग्रेस जनवरी पहले सप्ताह से ही अम्बेडकर को लेकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। डॉ. आंबेडकर दलित समुदाय के प्रतीक हैं। उन पर की गई किसी भी नकारात्मक टिप्पणी से इस समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है, जिससे भाजपा को आगामी चुनावों में नुकसान हो सकता है।

दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों की चुनौती- 2025 में भारत के दो प्रमुख राज्यों, दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इन चुनावों के परिणाम न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, जिससे मोदी सरकार की आगामी नीतियों और रणनीतियों की दिशा निर्धारित होगी।

दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए चुनाव फरवरी 2025 में संभावित हैं। वर्तमान में, आम आदमी पार्टी सत्ता में है और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना हैं। कांग्रेस ने अब तक 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। वर्तमान में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है।

विपक्षी एकता और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव- नये साल मोदी सरकार को विपक्ष से कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होंगी। सबसे पहले विपक्ष का विरोध एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर झेलना होगा। विपक्ष इसे संघवाद के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगा सकता है।

विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस, अडानी समूह से जुड़े विवादों को लेकर सरकार की पारदर्शिता और कॉर्पोरेट कनेक्शन पर सवाल उठाता रहेगा। विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। मणिपुर जैसी जगहों पर हुई हिंसा और सामाजिक असंतोष को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहेगा। ये मुद्दे सरकार की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़ा कर सकते हैं।

विपक्ष सामाजिक न्याय और आरक्षण के विषयों को आक्रामक रूप से उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर सकता है। विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा। विपक्ष चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर सरकार की विदेश नीति पर हमला बोल सकता है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के संदर्भ में।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

(4) ब्रह्माण्ड की स्थिति और तदन्तर्गत लोकों की कल्पना । (5) तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् (1। 25) सूत्र के, योग. भाष्य में ईश्वरावतारों का उल्लेख । (6) विभूतिपाद के योगभाष्य में अनेक सिद्धियों का वर्णन। (7) जथाभिमतध्यानाद्वा (समाधि) के भाष्य में प्रतीकोपा- सना की आवश्यकता। कहां तक लिखें पुराणवर्णात किसी भी सिद्धान्त को ले लीजिये, वेदान्तसूत्रादि में उसी का समाधान मिल जायगा। सैद्धान्तिक समता का तो जिक्र ही क्या है ? कई स्थलों में तो आक्षरिक समता का भी पर्याप्त मेल पाया जाता है। हम योगभाष्य और श्रीमद्भागवत के कतिपय प्रमाण यहाँ उद्धृत करते हैं, जिनसे उक्त दोनों ग्रन्थों की श्राक्षरिक समता का परिचय मिल सकता है।

यह पृथ्वी सात द्वीपों वाली है। जिसके बीच में पर्वतों का राजा सुवर्ण की खानों वाला सुमेरु पर्वत यूराल पहाड़ है। महाकाल, अम्बरीष रौरव, महारौरव, कालसूत्र, अंधतामिस्र आदि नरक हैं, जिनमें अपने कर्मों का दु:ख भोगने वाले प्राणी रहते हैं। महातल आदि सात पाताल हैं। जम्बूद्वीप (यूरेशिया) के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान् (काला सुफेद और हिन्दुकुश) नाम तीन पर्वत हैं उनकी लम्बाइयों के नीचे तीन देश रमणक, हिरण्मय और उत्तरकुरु हैं। दक्षिण में निषध, हेमकूट और हिमशैल (चम्बल नदी के ऊपर का पहाड़, घाघरा नदी से पूर्व का पहाड़ और घाघरा सतलुज के बीच का पहाड़) हैं, उनकी लम्बाइयों के नीचे हरिवर्ष, किंपुरुष और भारतवर्ष ये तीन देश हैं । सुमेरु की पूर्वदिशा में माल्यवान् पर्वत की सीमा वाला भद्राश्व वर्ष (मंगोलिया) आदि देश और सुमेरु की पश्चिम दिशा में गन्धमादन पर्वत की सीमा वाला केतुमालवर्ष (अरब आदि देश) हैं। जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत (साइबेरिया) देश है । इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि योगसूत्रादि ग्रन्थों के निर्माता व्यास जी ही अष्टादश पुराणों के बनाने वाले हैं। **(क्रमश:)**

विश्व अंतर्मुखी दिवस

विश्वबंधु पांडे

आज विश्व अंतर्मुखी दिवस है। हर साल 2 जनवरी को दुनिया भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इन दिन लोगों को अंतर्मुखी लोगों की आंतरिक दुनिया के बारे में जागरूक किया जाता है। लोगों को यह बताया जाता है कि अंतर्मुखी होने का मतलब यह नहीं है कि लोग समाज में काम नहीं कर सकते हैं। बल्कि अंतर्मुखी का संबंध सिर्फ इस बात से है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे सहज पाता है। तो चलिए आज विश्व अंतर्मुखी दिवस हम जानेंगे कि अंतर्मुखी किसे कहते हैं? और लोगों में अंतर्मुखी व्यक्ति को लेकर क्या-क्या गलत धारणाएं हैं?

अंतर्मुखी क्या है?

दरअसल इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो किसी से भी बात कर लेते हैं। जिन्हें घूमना, फिरना, दोस्त बनाना पसंद होता है। और दूसरे वह जो कम बोलते हैं, अकेले रहते हैं और अपनी बात बहुत कम या अपने किसी खास को ही बता पाते हैं। ऐसे लोगों को अंतर्मुखी कह सकते हैं।

इस दिन को मनाने का श्रेय जानी-मानी जर्मन साइकोलॉजिस्ट और राइटर फेलिसिटास हेने को जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत आज ही के दिन साल 2011 में हुई थी। फेलिसिटास हेने ने इस दिवस के जरिए इंट्रोवर्ट लोगों की खासियत के बारे में दूसरे लोगों को जागरुक करने का प्रयास किया था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अंतर्मुखी लोग अजीब होते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे किसी बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। यही गलतफहमियां दूर करने और उनके प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाने के मकसद से इस दिन की शुरुआत हुई थी।

अंतर्मुखी व्यक्ति को लेकर गलत धारणाएं

ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्ति शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। शर्मीलापन और अंतमुर्खी अलग व्यक्तित्व है। सच ये है कि ये लोग बिना कारण के बात करना पसंद नहीं करते है। कई लोग यह सोचते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्ति किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं जबकि सच यह है कि ऐसे लोग अपनी रुचि की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों की धारणा है कि अंतर्मुखी व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। बता दें कि अंतर्मुखी व्यक्ति को भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना उतना ही अच्छा लगता है, जितना किसी और को, लेकिन उनके उत्साह को अभिव्यक्त करने का तरीका अलग है।

लोगों का मानना होता है कि अंतर्मुखी व्यक्ति किसी से दोस्ती करना पसंद नही करते हैं जबकि असल में अंतर्मुखी लोग किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते है।

कई लोगों को लगता है कि अंतर्मुखी व्यक्ति नकारात्मक होते हैं हालाँकि यह सच नहीं है। कई लोग यह भी मानते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग अधिक रचनात्मक होते हैं जबकि रचनात्मकता का अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं है।

भारतीयों को लेकर आमने सामने आ गए ट्रंप और मस्क

अभिनय आकाश

पुरानी कहावत है कि अभी गांव बसा नहीं और फसाद पहले ही शुरू हो गए। 20 जनवरी का दिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। लेकिन ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही नया बवाल मचा है। पूरी कहानी समझने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। ट्रंप जब इलेक्शन में गए थे तब उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) का नारा दिया। इसमें उन्होंने बताया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तब होगा जब अमेरिकन्स के द्वारा अमेरिकियों को ही नौकरी दी जाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एन1बी वीजा सबसे बड़ी बाधा बना। दरअसल, अमेरिका हर साल लगभग 65 हजार से 85 हजार के बीच में स्किल्ड लेबर्स को तीन साल तक अपने यहां काम करने की परमिशन देता है। इसी परमिशन को जिस नाम पर दिया जाता है उसे एच1बी वीजा कहते हैं।

उदाहरण के लिए अगर आप किसी के घर जाते हैं तो डोर बेल बजाकर उसे सूचित करते हैं और ये एक तरह का मे आई कम इन वाला जेस्चर होता है। ऐसा ही कुछ आप किसी देश में जाते हैं तो उसी परमिशन को वीजा कहा जाता है। अगर आपको किसी देश में जाना है तो वहां की एबेंसी से परमिशन लेनी होती है। इस दौरान पूछा जाता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। काम करने, रहने या घूमने के लिए। स्थायी रूप से वहां रहने के लिए जाने वाली अनुमति को इमीग्रेंट परमिशन कहते हैं। अक्सर ऐसी परमिशन नहीं दी जाती है। अमेरिका किसी भी बाहर वासी को इंटरटेन नहीं करता है। लेकिन घूमने जाने वाले को गैर अप्रवासी कहा जाता है और अलग अलग सीमा के साथ उन्हें परमिशन दी जाती है। ऐसे ही अमेरिका में काम करने के लिए एच1बी वीजा के तहत परमिशन मिलती है। जिसमें गैर अप्रवासी जो स्किल्ड हैं, उन्हें एक बार में तीन साल तक वहां काम करने की परमिशन होती है। वो वहां न केवल खुद काम कर सकते हैं बल्कि अपने साथ अपने परिवार को ले जा सकते हैं। इतना बड़ा बैकग्राउंड बताने के पीछे का मकसद ये है कि इसी एच1बी वीजा के चक्कर में अमेरिका में बवाल मचा है।

अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यह वीजा जारी करती है। टेक्नॉलजी, मेडिसिन और बिजनेस में बेहद कुवाल लोगों को यह अस्थायी वर्षी दीजा जारी किया जाता है। 2023 में जारी हुए 2 लाख 65 हजार वीजा में सबसे ज्यादा 72.3% हिस्सा भारतीयों को मिला। करीब 12% चीजा चीनियों को मिले। इस वीजा के जरिए मुख्य रूप से 17 कंपनियां अमेरिका में अपनी क्लाइंट कंपनियों के काम के लिए भारतीय इंजिनियरों को भेजती है, जो अमेरिकी इंजिनियरों ज्यादा कुशल होने के साथ उनके मुकाबले कम वेतन में काम करते हैं। 2023 में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विपो को करीब 20,000 एच 1 बी वीजा की मंजूरी मिली थी। अमेरिका के लिए भी यह वीजा अहम है क्योंकि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में अमेरिकी लोग भारत और चीन के लोगों से काफी पीछे हैं, जिसे लेकर बराक ओबामा से लेकर बाइडन तक, तमाम नेता चिंता जताते रहे हैं।

खुद ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में बखेड़ा खड़ा किया था। तब भारत की ओर से दिए वीजा आवेदन बड़ी संख्या में खारिज किए गए। हाल यह हुआ कि खुद पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने तीन अलग- अलग मौकों पर यह मुद्दा उठाया। ताजा विवाद उठा है भारतवशी श्रीराम कृष्णन की नियुक्ति पर। ट्रंप ने अपने प्रशासन में एआई नीति की कमान संभालने का जिम्मा कृष्णन को सौंपा। कृष्णन को एच1बी वीजा समर्थक माना जाता है। दक्षिणपंथी भी और टूर की करीबी मानी जाने वाली लॉरा लूमर ने इसका विरोध किया। लौरा ने एक्स पर लिखा कि यह संच अमेरिका फर्स्ट नहीं है। इसके बाद ट्रप ही देशाड़ हो गई। एक खेमा एच-1बी पर बैन सामने की मांग कर रहा है, दूसरा इसके खिलाफ है।

मस्क ने ऐसे दावे करने वालों को बेवकूफ करार देते हुए कहा कि इस वीजा के जरिए दुनिया का टॉप 0.1% इंजिनियरिंग टैलेंट अमेरिका आता है। उन्होंने लिखा, स्पेसर, टेस्ला और सैकड़ों दूसरी कंपनियों ने अमेरिका करें मजबूत बाया है। मैं भी एच 1 बी वीजा के चलते ही अमेरिका में हूं। उन्होंने कहा कि वीजा प्रोग्राम के समर्थन में वह जंग छेड़ने के स्तर पर भी जा सकते है।

आज अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा योगदान है। एलन मस्क ने ट्रंप के लिए ही पूरे ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर ने कभी ट्रंप के अकाउंट को ही हटा दिया था। इससे उन्हें बेइज्जती भी महसूस हुई थी और बदले में ट्रंप ने अपना ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ट्रंप के एकाउंट को भी बहाल किया। मस्क ट्रंप के गहरे विस्वत व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। पूरे चुनाव में ट्रंप के खिलाफ बड़े बड़े बुद्धिजीवी खड़े थे। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ट्रंप की खिलाफत कर रही थी। एलन मस्क ने अपनी तरफ से ट्रंप का खुलेआम समर्थन ही नहीं किया बल्कि चुनाव में 2 हजार करोड़ से ऊपर का फंड भी दिया। लेकिन एच1बी वीजा ने दोनों के बीच रार पैदा कर दी है।

ट्रंप ने इस बार मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने तो हमेशा से ही एच 1 बी वीजा को पसंद किया है, मैं हमेशा से ही इसका पक्षधर रहा हूं। इसी वजह से तो हमने इसे जारी रखा है। मेरी प्रॉपर्टी पर खुद कई के पास एच 1 बी वीजा है। मैं तो इस पॉलिसी में पूर्ण विश्वास रखता हूं, खुद इसका कई बार इस्तेमाल किया है। यह एक बेहतरीन योजना है। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट से ट्रंप मस्क फर्स्ट पर शिफ्ट हो गए हैं। ट्रंप क्योंकि खुद एक उद्योगपति रहे हैं, उनकी राजनीति भी उसी के इर्ग-गिर्द घूमती है। वे कई ऐसे बदलाव चाहते हैं जिनमें उद्योगपतियों का समर्थन जरूरी रहेगा। ऐसे में एलन मस्क को साथ रखना उनके लिए जरूरी है।

आज का इतिहास

1971 स्कॉटलैंड के ग्लासगो के इब्रो पार्क में, एक ओल्ड फर्म फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 66 लोग मारे गए थे।
1975 बिहार के समस्तीपुर में जिले में एक बम विस्फोट में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा घायल हुए।
1975 हिरासत में बांग्लादेश के क्रांतिकारी नेता सिराज सिक्कर को पुलिस ने जान से मार दिया।
1976 जनवरी 1976 का गेल शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिणी उत्तरी समुद्र तटों के आसपास तटीय बाढ़ आ गई, जिससे कम से कम 82 मौतें हुईं और 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
1980 ब्रिटिश स्टील कॉर्पोरेशन प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों ने पचास साल में पहली हार राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की थी।
1981 अंग्रेजी सीरियल किलर पीटर सुटक्लिफ, यॉर्कशायर रिपर को शेफ़ील्ड में गिरफ्तार किया गया था, जो ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस जांच में से एक थी।
1989 प्रधान मंत्री रानीसिंह प्रेमदासा ने श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया।
1989 लोकप्रिय नाट्यकर्मी सफदर हाशमी को एक नाटक के दौरान असामाजिक तत्वों ने इतनी बेहरमी से पीटा कि उनकी मौत हो गई।
1994 द अबे लिंकोल्न इन ल्लीओंस 40 प्रदर्शनों को पूरा करने के बाद ब्यूमोंट न्यूयॉर्क शहर में बंद कर दिया गया।
1995 हवाई में वैज्ञानिकों ने केक टेलिस्कोप का उपयोग करके सबसे दूर की आकाशगंगा को पाया।
1997 हॉवर्ड स्टर्न रेडियो कोलंबस में प्रीमियर दिखाता है। ओहियो WBX 99.7 FM पर है।
1998 नाइजर के प्रधान मंत्री हामा अमादाउ को राष्ट्रपति इब्राहीम बारेमआनससेरा की हत्या के षड़यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
2004 स्टारडस्ट अंतरिक्ष जांच ने धूमकेतु वाइल्ड 2 से उड़ान भरी और इसके कोमा से कण के नमूने एकत्र किए, जो बाद में पृथ्वी पर वापस आ गए थे।
2008 सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली समन हसनैन वर्ष 2002 की मिसेज पाकिस्तान वर्ल्ड चुनी गईं।
2010 28 वर्षीय सोमाली पुरुष को ज्योलैंड्स-पोस्टेन मुहम्मद कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टरगार्ड के घर में घुसने के लिए गोली मार दी गई थी और उनके परिवार को कुल्हाड़ी से मारने की धमकी दी गई थी।

उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार के महासूर्य का अस्त होना!

ललित गर्ग

भारत के धुरंधर अर्थशास्त्री, प्रशासक, कद्दावर नेता, दो बार प्रधानमंत्री रह चुके डॉ. मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से आर्थिक सुधार का महासूर्य अस्त हो गया, भारतीय राजनीति में एक संभावनाओं भरा राजनीति सफर ठहर गया, जो राष्ट्र के लिये एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। वे निश्चित ही आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण के नींव के पत्थर थे, मील के पत्थर थे। वे आर्थिक सुधार की बुलंद आवाज थे। उन्हें आर्थिक सुधार, भारत में वैश्विक बाजार व्यवस्था एवं उदारीकरण का जनक कहा जा सकता है। जिन्होंने न केवल देश-विदेश के लोगों का दिल जीता है, बल्कि विरोधियों के दिल में भी जगह बनाकर, अमिट यादों को जन-जन के हृदय में स्थापित कर हमसे जुदा हो गये हैं। डॉ. सिंह यह नाम भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ है, जिससे एक सशक्त राष्ट्रनायक, स्वप्नदर्शी राजनायक, आदर्श चिन्तक, भारत में नये अर्थ के निर्माता, कुशल प्रशासक, दार्शनिक के साथ-साथ भारत को आर्थिक महाशक्ति का एक खास रंग देने की महक उठती है। उनके व्यक्तित्व के इतने रूप हैं, इतने आयाम हैं, इतने रंग है, इतने दृष्टिकोण हैं, जिनमें वे व्यक्ति और नायक हैं, दार्शनिक और चिंतक हैं, प्रबुद्ध और प्रधान है, शासक एवं लोकतंत्र उन्नायक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. सिंह के निधन पर कहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना आसान बात नहीं है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।'

दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह ने पांच दशक तक सक्रिय राजनीति की, अनेक पदों पर रहे, केंद्रीय वित्त मंत्री व प्रधानमंत्री- पर वे सदा दूसरों से भिन्न रहे, अनूठे रहे। घाल-मेल से दूर। भ्रष्ट राजनीति में बेदाग। विचारों में निडर। टूटते मूल्यों में अडिग। घेरे तोड़कर निकलती भीड़ में मर्यादित। वे भारत के इतिहास में उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ अपने नाम, व्यक्तित्व और करिश्मे के बूते पर न केवल सरकार चलाई बल्कि एक नयी सोच की राजनीति को पनपाया, पारदर्शी एवं सुशासन को सुदृढ़ किया। विलक्षण प्रतिभा, राजनीतिक कौशल, कुशल नेतृत्व क्षमता, बेबाक सोच, निर्णय क्षमता, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के कारण कांग्रेस के सभी नेता उनका लोहा मानते रहे, उनके लिये वे मार्गदर्शक ही नहीं, प्रेरणास्रोत भी है। वे बेहद नम्र इंसान थे और वह अहंकार से कोसों दूर थे। उनके प्रभावी एवं बेबाक व्यक्तित्व से भारतीय राजनीति एवं लोकतांत्रिक संस्थान चमकते रहे हैं। डॉ. सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही, उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर, निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉ. सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहित किया गया।

डॉ. सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितम्बर 1932 को हुआ था। उनकी जन्मतिथि भी 26 एवं निधन तिथि भी 26 एक संयोग ही कहा जायेगा। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। डॉ. सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी हैं। उनके तीन बेटियां हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गये। जहाँ से उन्होंने पीएच. डी. की। तत्पश्चात् उन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी. फिल. भी किया। डॉ सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकनामिक्स में प्राध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉ सिंह भारत के

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किये गये। इसके तुरन्त बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमन्त्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉ सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मन्त्री रहे। डॉ. सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दो कार्यकाल पूरे किए हैं।

पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम भी उनके कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, इस दौरान उन्हें 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा। यह बात हम सभी जानते हैं कि उन्हें मौन पीएम भी कहा जाता था, हालांकि उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से इसका सटीक जवाब भी दिया था। विकास के प्रति डॉ. सिंह की प्रतिबद्धता और उनकी अनेक उपलब्धियों को उन अनेक सम्मानों के माध्यम से मान्यता मिली है जो उन्हें प्रदान किए गए हैं। इनमें 1987 में पद्म विभूषण, 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार शामिल हैं। जवाहर लाल नेहरू के बाद मनमोहन दूसरे ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर दो कार्यकाल पूरा किया। उन्हें अपने फैसलों के लिए काफी अडिग माना जाता है।

2004 से 2014 तक, भारत दसवें स्थान से उठकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिससे लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधरा और गरीबी में कमी आई। डॉ. सिंह के दृष्टिकोण में केवल उच्च विकास नहीं, बल्कि समावेशी विकास और उस विश्वास की भी अहमियत थी जो सभी को ऊपर उठाने वाली लहरें उत्पन्न कर सके। यह विश्वास उनके द्वारा पारित किए गए विधेयकों में दिखाई देता है, जिनसे नागरिकों को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और सूचना का अधिकार सुनिश्चित हुआ। डॉ. सिंह की अधिकार-आधारित क्रांति ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करने का संकल्प था। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में समृद्धि और विकास की कहानी लिखी गयी। जुलाई 1991 में, डॉ. सिंह ने अपने बजट भाषण के अंत में कहा था, 'भारत का दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय एक ऐसा विचार है, जिसका समय अब आ चुका है।' डॉ. सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र, मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं के लिए याद किया जाएगा, जिनसे उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया।

डॉ. सिंह के राजनीतिक जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आये, जब सार्वजनिक तौर पर उनकी प्रतिष्ठा और उनके पद को कमतर दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी देश के लिए जीने और मरने की कसम खाने वाले डॉ. सिंह ने देश हित में अपमान के ये घूंट भी चुपचाप पी लिए। डॉ. मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया। 2019 में इसी नाम से फिल्म आई। यह संजय बारू की किताब पर बनी थी। डॉ. सिंह देशहित में नीतियां बनाने एवं राजनीति की नयी दिशाएं तलाशने में माहिर थे, उनका जीवन सफर राजनीतिक आदर्शों की ऊंची मीनार हैं, राजनीति का एक प्रकाश है। उनका निधन एक युग की समाप्ति है। वे गहन मानवीय चेतना के चितेरे जुझारु, नीडर, साहसिक एवं प्रखर व्यक्तित्व थे। बेशक डॉ. सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपने सफल राजनीतिक जीवन के दम पर वे हमेशा भारतीय राजनीति के आसमान में एक सितारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे।

भारतीय राजनीति में सादगी, कर्मठता, ईमानदारी एवं राजनीतिक कौशल से अपनी जगह बनाने वाले एवं निरन्तर चमत्कार घटित करने वाले डॉ. सिंह अपनी प्रभावी एवं शालीन भूमिका से देश की आर्थिक मजबूती की एक बड़ी उम्मीद बने थे। उनका समूचा जीवन राष्ट्र को समर्पित एक जीवन यात्रा का नाम है- आशा को अर्थ देने की यात्रा, ढलान से ऊंचाई की यात्रा, गिरावट से उठने की यात्रा, मजबूरी से मनोबल की यात्रा, सीमा से असीम होने की यात्रा, जीवन के चक्रव्यूहों से बाहर निकलने की यात्रा। मन बार-बार उनकी तड़प को प्रणाम करता है। उस महापुरुष के मनोबल को प्रणाम करता है!

कम्युनिस्ट पार्टी में जहां खूबियां हैं, वहीं खामियां भी

मंगत राम पासला

वर्ष 2008 से अमरीका में शुरू हुआ आर्थिक संकट यद्यपि दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है, जिसने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था मानवता का कल्याण करने में पूर्णत: असमर्थ है। वर्तमान संकट शुरू होने के समय ईसाई धर्म के सर्वोच्च धार्मिक नेता पोप ने कहा था, ''जर्मनी में जन्मे एक महान व्यक्ति कार्ल मार्क्स ने हमें पूंजीवादी व्यवस्था में होने वाले आर्थिक धमाकों के बारे में पहले से ही सचेत कर दिया था परन्तु हम उसकी भविष्यवाणियों की ओर ध्यान नहीं दे सके।'' कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी का सार यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के मामले में विफल रही है जबकि समाजवाद यानी समानताओं वाले समाज में इन कार्यों को पूरा करने की अपरिहार्य संभावनाएं हैं। भारत में 1947 के बाद से विभिन्न रंगों की सरकारों के प्रदर्शन और आम लोगों की बढ़ती कठिनाइयों को देखते हुए बुद्धिमान नागरिक अक्सर सवाल करते हैं कि क्या व्यावहारिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से जनसमर्थक होने के बावजूद वामपंथी विचारधारा अभी भी प्रासंगिक है? वर्तमान समय में कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर क्यों होती जा रही हैं। समाज में संघर्षशील होते हुए भी वे लुटे-पिटे लोगों के बीच अपना प्रभाव एवं जनाधार क्यों नहीं बढ़ा सकीं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि वामपंथी दलों की ताकत कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, जो उन्हें वर्तमान सरकारों की जनविरोधी नीतियों और समाज को बांटने वाले साम्प्रदायिक विचारों का विरोध करने में सक्षम बना सके। वामपंथी ताकतों के बारे में कोई संदेह नहीं है। सही सोच रखने वाले लोगों विशेषकर श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश लोगों के दिलों में वाम आंदोलन को मजबूत देखने की प्रबल इच्छा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। वामदलों ने अपनी मानवतावादी विचारधारा, स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए गौरवपूर्ण बलिदानों, श्रमिकों, किसानों, भूमिहीन मजदूरों सहित समाज के हर पीड़ित वर्ग की समस्याओं को हल करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जन संघर्षों के रूप में सबसे अधिक योगदान दिया है। राजनीति को सत्ता का सुख भोगने और भ्रष्टाचार तथा लूटपाट के माध्यम से अकूत धन संचय करने का हथियार मानने वाले राजनेताओं के एकदम विपरीत कम्युनिस्टों के लिए 'राजनीति' जनसेवा का सर्वोत्तम हथियार है, जो पूरे समाज को सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकता है। राजनीतिक पैंतरेबाजी में कम्युनिस्टों ने भी कई गलतियां की हैं। लेकिन ऐसी अधिकांश चूकें किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं बल्कि समय की परिस्थितियों का सही आकलन न कर पाने या आत्ममंथन और गलत निर्णय के कारण होती हैं। इन सभी कमियों के बावजूद भारत की राजनीति में कम्युनिस्टों की एक विशिष्ट पहचान आज भी अवश्य बनी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टियों को सार्वजनिक क्षेत्र का मूल्यांकन करते समय एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही राजनीति करते हैं। आर्थिक नीतियों के मामले में इनमें कोई बुनियादी अंतर नहीं है। इसलिए कुछ बिंदुओं पर मतभेद होने के बावजूद शासन चलाने का तरीका करीब-करीब एक जैसा है। इसके विपरीत कम्युनिस्ट वर्तमान ढांचे के संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए भी यथासंभव लोगों के कल्याण की संभावनाएं तलाशते रहते हैं लेकिन अंत में वे मौजूदा व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल देते हैं और एक नई राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसलिए अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में कम्युनिस्टों के लिए आम जनता को वैचारिक रूप से सहमत कर संगठित करना कठिन कार्य है।

हमारे नेताओं को 2025 एक बेहतर वर्ष बनाना होगा

पूनम आई. कौशिश

वर्ष 2024 का विदाई उल्लेख किस तरह करें? नई आशाओं और नए वचनों के साथ वर्ष 2025 का स्वागत करते हुए शैंपेन की बोतल खोलें या अगले 12 महीनों तक निरंतर पतन देखते रहें। स्पष्ट है कि वर्ष 2024 को इतिहास में एक उथल-पुथल भरे वर्ष के रूप में देखा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से वर्ष 2024 में एक विकृत, नई निकृष्ट बात देखने को मिली। भाजपानीत राजग और कांग्रेस के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर कुछ विवाद देखने को मिला। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार राजघाट पर करने की बजाय सार्वजनिक घाट पर करने से उनका अपमान किया गया है और उनके स्मारक के लिए भूमि नहीं दी गई। भाजपा ने इसका प्रत्युत्तर कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए दिया कि यह राजनीतिक लाभ के लिए छोटी मनगढ़ंत बातों से इस दुख की घड़ी का दोहन कर रही है।

कांग्रेस भूल गई है कि उन्होंने अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव के अंतिम संस्कार के समय कैसा व्यवहार किया था और उनके लिए दिल्ली में स्मारक के लिए भूमि नहीं दी थी। उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में रखने नहीं दिया गया और राव परिवार से कहा गया कि वे उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में करें, स्मारक बनाना तो दूर की बात है। राव का स्मारक राष्ट्र एकता स्थल मोदी सरकार द्वारा बनवाया गया। उसके बाद भाजपा ने कांग्रेस के प्रथम परिवार सोनिया-राहुल पर अमरीकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों और उसके साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने के लिए भारत विरोधी एजैंडा चलाने का शोर मचाया और यहां तक कि इस मुद्दे पर सपा और तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया। उसके बाद 'मेरा आंबेडकर बनाम तुम्हारा आंबेडकर' को लेकर विवाद देखने को मिला।

चुनावी दृष्टि से वर्ष 2024 के आम चुनावों में मोदी को नुकसान उठाना पड़ा और मोदी 3.0 में इस बार 400 पार

की बजाय गठबंधन सरकार बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। निश्चित रूप से भाजपा को अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 240 सीटें मिलीं और सहयोगी दलों के साथ 293, किंतु क्या मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अपनी शर्तों के अनुसार कार्य कर पाएंगे? उसके बाद भाजपा महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों के साथ भारी जीत दर्ज कर भूल सुधार करने में सफल रही। साथ ही हरियाणा में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की, हालांकि लोकसभा चुनावों में इन दोनों राज्यों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस अपनी विफलता से कोई सबक नहीं ले रही। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस स्थिति से कैसे उबरती है।

वर्तमान में इंडिया गठबंधन में तकरार चल रही है। तृणमूल कांग्रेस की ममता की तरह इस बार दिल्ली में केजरीवाल भी अकेले चुनाव लडऩे जा रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वह इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इस राजनीतिक आक्रोश के बीच आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहा है तथा उसमें आक्रोश और असंतोष बढ़ रहा है। जनता अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है और नए वर्ष में बदलाव की आशा रख रही है।

सामाजिक क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी नहीं है। स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्यान्न के क्षेत्र में अरबों-खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद 70 प्रतिशत लोग अभी भी भूखे, अशिक्षित, अकुशल और बुनियादी चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। कहीं भी चले जाएं, स्थिति एक जैसी है जिसके चलते लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और हिंसा करने पर उतारू हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जघन्य हत्याएं देखने को मिल रही हैं और ऐसा लगता है कि सारा देश अंधेर नगरी में बदल रहा है। महिलाओं का यौन उत्पीडऩ, उनके साथ छेड़छाड़ आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। देश में प्रत्येक मिनट में 7 बलात्कार होते हैं। निर्भया से लेकर हाथरस तक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। विदेशी मोर्चे पर चीन के साथ भारत के संबंधों में विशेष सुधार नहीं हुआ। लंबी बातचीत के बाद मोदी चीन को इस बात से सहमत कराने में सफल हुए हैं कि पूर्वी लद्दाख, देपसांग और गलवान घाटी में शांति और स्थिरता बहाल की जाए, जहां पर जून 2020 में नियंत्रण रेखा पर चीन ने आक्रामक कार्रवाई की थी। चीन न्यू नार्मल बनाना चाहता है, किंतु भारत को बुद्धिमता, परिपक्वता और धैर्य के साथ रणनीति अपनानी होगी, ताकि वह भारत-चीन संबंधों को नियंत्रित कर सके।

देश 2025 में प्रवेश कर रहा है, हमारे नेतागणों को जिम्मेदारी से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होगा, अपने तौर-तरीकों को बदलना होगा तथा शासन के वास्तविक गंभीर मुद्दों का निराकरण करना होगा। उन्हें इस बात को समझना होगा कि भारत की लोकतांत्रिक शक्ति आम जनता की सहनशीलता और धैर्य में है। इसके अलावा सरकार व विपक्ष दोनों को अपने नेताओं के साथ मिलकर इस बात पर विचार करना होगा कि यदि दोनों पक्ष मिलकर कार्य करेंगे तो एक बहुलवादी समाज का निर्माण होगा, जहां पर विभिन्न समुदायों के लोग मिलकर रहेंगे, जो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर, हमारे शासकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वे वर्ष 2025 को किस तरह से एक बेहतर वर्ष बता सकते हैं। उन्हें अपने बुनियादी कर्त्तव्यों पर ध्यान देना होगा और अधिक मानवीयता के साथ कार्य करने होंगे। उन्हें विश्व को आशा के एक नए लैंस से देखना होगा, जहां पर सम्यक प्राधिकार, सम्यक इरादे और सम्यक आशाएं हमारे प्रत्युत्तर का निर्धारण करें।

नये साल में प्रखर होंगी लोकतंत्र की किरणें?

राजेश बादल

वर्तमान सदी अपनी चौथाई उमर पूरी कर चुकी है। यानी अब यह एक गबरू जवान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। पच्चीस बरस का हो रहा यह शताब्दी नौजवान वास्तव में मानसिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है? कह सकता हूं कि उसकी देह या कदकाठी तो मजबूत है लेकिन दिमागी तौर पर यह सदी अभी बालिग नहीं दिखाई देती। मां बनने की क्षमता तो यह शताब्दी रखती है मगर संसार को संस्कारवान बना रही है, इसमें अभी संदेह है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? हजार साल की लंबी गुलामी के बाद हमारे सामने अपना लोकतंत्र तो आ गया लेकिन हमारे भीतर वह संकल्प बोध नहीं था, जो किसी नवोदित आजाद मुल्क के भीतर होना चाहिए था। अंगरेज हमें देश थमाकर चले गए पर हम अपने पर राज करने की मौलिक शैली भूल चुके थे।

सदियों तक परतंत्र रहते हुए भारत अपनी गणतांत्रिक जड़ों से अलग हो चुका था और बिना जड़ों के हम अपनी शासन शैली को जमीन में खोज रहे थे। यह ठीक है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक पुरुषों ने आजाद होने से पहले ही इस कमजोरी को भांप लिया था। इस कारण विश्व का श्रेष्ठ संविधान रचने की कवायद होती रही।

जब संविधान नामक नियामक संस्था हमारे बीच आई तो उन पूर्वजों या प्रतीक पुरुषों ने उसे अपनी गीता मानकर राष्ट्र में संविधान के नये बीजों से लोकतांत्रिक फसल लेने का प्रयास किया। यह प्रयोग कामयाब

रहा। शायद इसलिए कि उस संविधान संस्था में हिंदुस्तान के बगीचे में मौजूद सारे फूल अपनी-अपनी सुगंध के साथ उपस्थित थे।

कोई एक फूल अपने आपको राजा फूल नहीं कह सकता था। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा लगने लगा कि शायद हमें स्वयं अपनी इस सुगंध से अरुचि हो गई है। उसका असर हमारी सियासत पर दिखाई दिया और धीरे-धीरे भारतीय उपवन से जम्हूरियत की यह खुशबू कम होती गई। पुराना सामंत बोध अपने नए विकृत स्वरूप में चुपचाप दाखिल होता रहा।

जाने-माने संपादक और दार्शनिक चिंतक राजेंद्र माथुर ने पचपन साल पहले इसकी शानदार मीमांसा की थी। मैं यहां उनकी एक लंबी टिप्पणी पेश करना चाहूंगा। राजेंद्र माथुर राम नाम से प्रजातंत्र शीर्षक से 26 जनवरी 1969 को लिखे आलेख में कहते हैं, ''जो हमने देखा है, वही कर रहे हैं। शासक विदेशी थे, इसलिए शासन प्रक्रिया भी हमारे लिए विदेशी हो गई।

अब स्वराज है लेकिन हालत ज्यों की त्यों है। हम इस देश को ऐसे लूट रहे हैं, जैसे यह देश हमारा नहीं, बल्कि और किसी का हो। एक माने में भारत पर आज भी उन्हीं शासकों का राज है। जनता और शासकों के बीच जो संगीतमय जुगलबंदी प्रजातंत्र में चलती है, वह हमारे यहां गायब है। मंत्री बनना या आईएएस परीक्षा में पास होना हमारे यहां इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

क्योंकि रेखा के उस पार जो विश्व है, वह अलग है। वह विजेताओं का विश्व है। अंगरेज चले गए, लेकिन रेखा के उस पार उनके साम्राज्य का प्रतिबिंब मौजूद है। जो आदमी नायब तहसीलदार बन जाता है, वह भी रेखा के उस पार चला जाता है और विदेशी लुटेरा बन जाता है। महात्मा गांधी अगर राज्य का महत्व कम करना चाहते थे तो उसके पीछे अनेक प्रबल कारण थे।

बड़ा कारण तो यह था कि हजार बरस से भूखे मरने वाले देश को पहले मौसंबी के रस की जरूरत थी, दाल व फलों की नहीं। गांधी अपने अंतर्मन में जानते होंगे कि भारत के बंदर ने कभी राज्य का उस्तरा पकड़ा ही नहीं है। शनै: शनै: इस देश की शासनेंद्रिय का विकास होगा। सत्ता की सीमा और जनता की महिमा यह देश सीख सके, इसके लिए कुछ वर्षों तक भारत को गांधी जैसे भक्त नेताओं की आवश्यकता थी, जो कुर्सी-मुखी नहीं, जन-मुखी होते। वे जनता को और शासकों को सिखाते कि अपने घर में नियम और संयम से कैसे रहा जाता है।

लेकिन हुआ यह है कि राम नाम से प्रजातंत्र की ओर करंट इतनी तेजी से बढ़ा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है और सारे देश में अंधेरा घुप्प है। यानी 15 अगस्त, 1947 के पहले भी अंधेरा था और अब भी है।'' वे लिखते हैं, एक हजार साल बाद लुटेरे गए हैं और हमारा घर हमें वापस मिला है। हम, जो प्रेतों की तरह बल्लियों और खपरैलों पर बैठे थे, अब नीचे आ गए हैं।

पर हम भूल गए हैं कि घर में कैसे रहा जाता है। वे कौन से संयम और स्नेह के तंतु हैं, रिश्तों का वह कौन सा ताना-बाना है, जो परिवार को गरिमा और संतोष प्रदान करता है- हमें नहीं मालूम। 55 साल पहले लिखा गया यह आलेख आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि आज 77 साल बाद भी हम दुविधा के इसी जाल में उलझे हुए हैं। हमने शासन करने के लिए एक प्रणाली तो बनाई, लेकिन उसको मानने के लिए राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं किया। आजादी के समय भले ही 18 फीसदी साक्षरता रही हो, पर उस समय के भारत में मानवीय और नैतिक मूल्यों का एक विराट भंडार उपस्थित था।

आज हम 75 प्रतिशत आधुनिकता के साथ उपस्थित हैं लेकिन राष्ट्रबोध नदारद है। यह एक निराशाजनक तस्वीर है। असल में ऐसी स्थिति तब बनती है, जब मुल्क सियासी ढांचे में ढलता तो है, पर उसमें जिम्मेदारी और सरोकारों वाला नेतृत्व नहीं होता। एक ऐसा प्रेरक नेतृत्व, जो हमारे समाज के सामने मुंह बाये खड़ी मुश्किलों को पार करने की हिम्मत और हौसला दे।

यह काम खंड-खंड समाज नहीं करता, बल्कि एकजुट देश ही करता है। याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भारतीय अगुआई भी दो हिस्सों में विभाजित थी। एक तरफ ओजस्वी, आजादी के आंदोलन से निकले तपे तपाए, विराट दृष्टिकोण वाले नेता थे तो दूसरी ओर संकीर्ण, अनुदार, कट्टर और छुटभैये नेताओं का बड़ा झुंड था।

नया साल चुनौतियों के समाधान का काल भी हो

दीपक कुमार शर्मा

नई सुबह और नए हौसलों के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अतीत की उपलब्धियों का गर्व और चुनौतियों का बोझ है, तो संभावनाओं के एक नए सूर्य का भी उदय हो रहा है। हमने बीते साल में उन स्थितियों को देखा, जब वैश्विक युद्धों और आपूर्ति श्रृंखला में लगातार पहुंच रही बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती रही। हमने एक करोड़ घरों में सौर रूफटॉप लगाने संबंधी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की ऐतिहासिक घोषणा भी

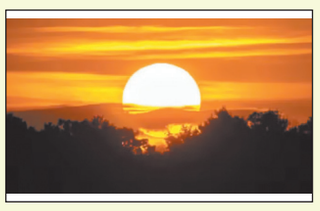

देखी, जिससे गरीब व मध्यम आय वाले परिवारों को बिजली के भारी-भरकम बिलों से निजात मिलेगी और ऊर्जा क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर बनने का भी मार्ग खुलेगा। चौबीस करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी से उबारना एक बड़ी उपलब्धि रही, तो हालिया स्पैडेक्स जैसे अभियानों के दम पर आज भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनींदा देशों के साथ खड़ा है। इन सबके बावजूद, जैसा अंग्रेजी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, 'मीलों अभी चलना है', कई चुनौतियां भी हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है। नए साल का मतलब सिर्फ तारीख का बदलना नहीं होता, बल्कि यह जीवन को एक नए ढंग से देखने और विफलताओं से सीखने व सबक लेने का भी अवसर हो सकता है। मसलन, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक राजनीति में जिस तरह की कटुता दिख रही है, वह खत्म होगी। संसद के कामकाज में रुकावटें दूर होंगी और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर मर्यादा को नहीं लांघेगा। विदेश नीति के मामले में, पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जिस तरह से भारत-विरोधी हवा चल रही है, उसे देखते हुए दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाए रखना भारतीय कूटनीति के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश समेत पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी भी एक बड़ी चिंता है। आर्थिक मोर्चे पर देखें, तो बढ़ती महंगाई के अलावा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की हालिया गिरावट, भले ही वह दूसरे देशों की तुलना में कम हो, आशंका पैदा करती है। भारत समेत दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं का बढ़ना और प्रदूषित होती हवा चिंताजनक है, लेकिन समृद्ध देशों के अनमनेपन के चलते पर्यावरणीय सम्मेलनों का महज औपचारिकता बनकर रह जाना उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है। उम्मीद है कि नया साल इन चुनौतियों के समाधान का काल भी होगा।

नव वर्ष 2025

विश्वभर में नया साल मनाने का तरीका भी अलग-अलग है. सभी धर्मो में नया साल एक उत्सव की तरह अलग-अलग अंदाज में अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. दुनिया में सबसे अधिक देशों में ईसाई नव वर्ष मनाए जाने की परंपरा है. ईसाई वर्ष 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक 12 महीनों में बंटा हुआ है. खास बात यह है कि भले ही दुनिया के सभी धर्मो के रीति-रिवाज अलग-अलग हों लेकिन 1 जनवरी को सभी देशों में नए साल की धूम रहती है. विश्व में वर्ष के अंतिम कुछ क्षणों में आतिशबाज़ी करते हुए पुराने साल को विदा और नव वर्ष का स्वागत किया जाता है.

क्या है न्यू ईयर की कहानी?

हजारों साल पहले प्राचीन बेबीलोन में न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी. परंतु उस समय नव वर्ष का यह उत्सव 21 मार्च को मनाया जाता था जो कि वसंत के आगमन की तिथि थी. जो हिन्दुओं का नववर्ष है. ग्यारह दिनों तक चलने वाले पर्व के रूप में यह वसंत ऋतु के पहले दिन से शुरू होता था. इसीलिए सितंबर सातवां, अक्टूबर आठवां, नवंबर नौवां और दिसंबर दसवां महीना माना जाता था. जैसा कि इनके नामों से स्पष्ट होता है. यह गणना रोमन कैलेंडर के अनुसार किया जाता था जो सातवीं शताब्दी बीसी से शुरू हुआ और यह चन्द्रमा के चक्र के मुताबिक था. रोमन कैलेंडर अटकलबाजी के बलबूते बनाया गया था. जो 1 मार्च से शुरू होता था. तब एक साल में 304 दिन और कुल 10 महीने हुआ करते थे. मार्च से लेकर दिसम्बर तक, इन महीनों के नाम इस तरह थे मर्सिअस, एप्रिलिस, मैयास, जूनियस, क्विन्तिलिस, सेक्सटिलिस, सेप्टेम्बर, ओक्टोबर, नोवेम्बर, और डिसेम्बर.लेकिन सन 1570 के आसपास पोप ग्रेगरी XIII ने क्रिस्टोफर क्लेवियस को एक नया कैलेंडर बनाने का जिम्मा सौंपा. इस तरह सन 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर अस्तित्व में आया. तब से पूरी दुनिया में नए साल का उत्सव बदस्तूर 1 जनवरी को मनाया जाता है.

न्यू ईयर पर अमेरिका की बॉल ड्रॉपिंग परंपरा

वैसे तो विश्व में वर्ष के अंतिम कुछ क्षणों में आतिशबाजी करते हुए पुराने साल को विदा और नव वर्ष का स्वागत किया जाता है परंतु अमेरिका में यह उत्सव अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ का 'बॉल ड्रॉपिंग' दुनिया का सबसे मशहूर बॉल ड्रॉपिंग कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क शहर के टाइस स्वायर पर न्यू इयर्स ईव की मध्यरात्रि को होता है। इससे पहले डाउनटाउन मैनहट्टन के ट्रिनिटी चर्च के घंटे को सुनने के लिए आधी रात में लोग जमा होते थे। द न्यूयॉर्क टाइस ने सन 1904 में जन मानस को आकर्षित करने के लिए न्यूयॉर्क टाइस की ईमारत पर जोरदार आतिशबाजी की। इससे लोग आकर्षित तो हुए लेकिन पटाखों के कारण सड़कों पर गरम राख और पटाखों के टुकड़ों की बरसात हुई जो कि हानिकारक होने के साथ कचरा जमा होने का भी कारण बना इन्हीं वजहों से न्यूयॉर्क पुलिस ने वहां आतिशबाजी करने के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। तब न्यूयॉर्क टाइस के मालिक एडोल्फ ऑस ने अपने चीफ इलेट्रिशियन वॉल्टर पाल्मर को नया रास्ता निकालने के लिए कहा। पाल्मर के डिजाइन के आधार पर ऑस ने आर्टक्राट स्ट्रॉस साइन कंपनी को लगभग 318 किलो की लोहे व लकड़ी से निर्मित और 25 वाट के 100 बल्बों से जड़ित बॉल बनाने की जिमेदारी दी। इस बॉल को पहली बार इलेट्रिसिटी का उपयोग कर सन 1908 के बॉल ड्रॉपिंग में प्रयोग किया गया।

भारतीय नव वर्ष

ग्रेगोरियन कलैंडर का अनुसरण वैसे तो पूरी दुनिया में हो रहा है लेकिन विभिन्न देशों में वहां की संस्कृति के अनुसार भी नया साल मनाने की परंपरा है। भारत में तो विभिन्न धर्म व संप्रदाय एक साथ रहते हैं। इन धर्मों व संप्रदायों के कैलेंडर भी अलग-अलग हैं अत: इनके नव वर्ष की तिथियां भी अलग-अलग होती हैं। हिंदू नववर्ष की बात करें तो यह चैत्र माह की शुल प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है जो कि अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के अनुसार मार्च-अप्रैल माह में पड़ता है।

नववर्ष को जिन्दगी का सबसे बड़ा वर्ष कैसे बनाये ?

लीजिये, हंसता और मुस्कुराता, खिलखिलाकर नव उल्लास बिखराता, निराशा को भगाता और आशा को बटोरता नया वर्ष फिर से आ गया। चारों ओर देखिये, पेड़ नये पत्तों और कलियों के आगमन से कैसे झूम रहे हैं। पेड़-पौधे मुक्तहस्त होकर सुगंध बांट रहे हैं। भला कौन वह मूर्ख होगा, जो परिवार में आ रहे नये सदस्यों को देख खुश न हो। पशु हो या पक्षी, मानव हो या वनस्पति; सब पुराने के जाने पर दुखी होते हैं; पर वह दुख नवआगत के स्वागत के कारण धूमिल भी हो जाता है। यही सृष्टि का नियम है, इसलिए आज सब खुश है। आखिर क्यों न हों, नया साल जो आया है।

दोस्तों, हर देश व संस्कृति में अलग अलग तारीख में नया वर्ष मनाये जाने की परम्परा पहले से ही चली आ रही है. लोग अलग अलग तरीके से इस आयोजन को मानते है, जैसे कोई दारू पीता है तो कोई पार्टी करता है, कही लोगो व्यर्थ में बैठे रहते है तो कोई मजे के नाम पर समय व पैसो की बर्बादी करता है. लेकिन कुछ लोग खुद में सुधार के लिए अच्छा काम भी करते है लेकिन समय बीतने के साथ ही वह अपने संकल्पों को जान-बूझकर तोड़ देते है और पुराने ढर्रे पर ही वापस आ जाते है. एक साल में ही 'ढाक के तीन पात' वाली स्थिति नज़र आने लगती है। वैसे भी किसी नयी शुरुआत के लिए नये साल या किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा ही क्यों करना ? इस बार हम नये साल क्या हर साल व हर क्षण को सार्थक करने के कुछ सरल तरीके बता रहे हैं जिसमे आपको अपने अंदर कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको इन्हें तुरंत ही तन-मन-धन से भी अधिक ध्यान से अपनाने की जरूरत होगी.

अपनी कमाई और खर्चो का लेखा-जोखा रखें -

दोस्तों, इस नव वर्ष में आपको सबसे पहले अपने खर्चे व होने वाली कमाई का एक लेखा जोखा जरुर रखना चाहिए. एक ऐसा लेखा जोखा बनायें जिसमें हर दिन के हिसाब से अपने प्रत्येक छोटे-से-छोटे खर्चे का भी उल्लेख करें किन्तु ध्यान रखें कि किसी को बुरा न लगे या किसी पर किया गया खर्चा 'अहसान जताने' जैसा न हो. हो सके तो ऐसा लगे भी ना ! आप अपना लेखा जोखा शुरू करोगे तो आपको अपने व्यर्थ खर्चो को ष्श्द्वह्लह्ण्द्ध कर सकोगे साथ ही साथ इससे आपको विलासादि जैसे व्यर्थ खर्चे न्यूनतम करते हुए शून्य करने व अच्छे काम में किये गये खर्चो को बढ़ाने में सहायता होगी।

ब्रह्ममुहूर्त में उठने की आदत बनायें -

दोस्तों, हमारे लिए सुबह उठना काफी फायदेमंद होता है और इससे हमारी बॉडी तरोताजा रहती है. सुबह जल्दी उठने से हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी होता है. इसलिए सुबह सूर्य की पहली किरण पहुँचने से पहले उठकर स्नान करने की आदत एक बार बना ली तो यह बात गाँठ बाँध लीजिए कि आप अपनी पुराणी स्थिति की अपेक्षा अधिक सहज रहेंगे. आपका समय-प्रबन्धन अब कुछ ठीक प्रकार से हो जायेगा व आप दिन-रात ताम-झाम में डूबी रहने वाली व टाइम नहीं है जैसी समस्याओं से दूर हो जाओगे. अब आपके पास समय ही समय होगा और अपने दिन भर के काम आप एक ही दिन में पूरे करने लगोगे.

अपनी डायरी मैण्टैन करें -

टी.वी. के सामने व्यर्थ बैठे रहने, शराब, धूम्रपान करने में जो आपने अपना नुकसान किया उसकी सारी विवरण, कार्य व समय इत्यादि के अनुसार प्रतिदिन इस प्रकार लिखें कि जिस दिन आप उस निरर्थकता से बचे तो आपको आनन्द आयेगा व संतोष का अनुभव होगा तथा गम्भीरता से पालन किया तो किसी दिन ऐसी स्थिति भी आ जायेगी कि आपको यह सब लिखने की जरूरत भी अनुभव नहीं होगी या आप पूरी तरह से सुधर चुके होंगे। जब भी कोई उल्लंघन करें तो अपने आप को कुछ सज़ा दें, जैसे कि अगले दिन चाय-काफ़ी बिल्कुल न पीयें, कल साईकल ही चलायें, कल 10-10 मिनटस तक कम से कम तीन बार रस्सी कूदें इत्यादि। ग़लती को दोहराने पर सज़ा की मात्रा व तीव्रता बढ़ा दें ताकि स्वयं को संदेश जाये कि अबकी बार अधिक सावधानी बरतनी है, या दण्ड झेलना और कठिन हो जायेगा।

मिट्टी के दो कटोरे में डेली पानी भरे -

हाट जाकर देसी मिट्टी से बने दो सकोरे लायें जिन्हें प्रतिदिन धो-धोकर एक सकोरे में पेयजल भरें व दुसरे में मिश्रित देसी साबुत अनाज को मिक्स करके रखे, स्थानीय किराना दुकान या अनाज-व्यवसायी से बोलें. समस्त देसी व साबुत अनाजों का एक मिश्रण तैयार कर दें। शहर हो या गाँव हर स्थिति-परिस्थिति में पक्षियों व गिलहरियों को स्वच्छ पेयजल व पौष्टिक व स्वादिष्ट शुद्ध भोजन की कमी की सतत पूर्ति का यह सबसे सरल उपाय है एवं हम सबके 'मनुष्य' होने को परिभाषित करता ईश्वरीय उत्तरदायित्व भी।

कील-तार-सीमेण्ट-क्रांक्रीट से करें मुक्त -

आपने देखा होगा की कई बार कई पेड़ - पौधे तार व अन्य चीजो से दब जाते है या उनके ऊपर किसी सामान का बोझ लदा रहता है जिस कारण वह पौधे या तो टूट जाते है या उनका विकास नहीं हो पाता. इसलिए हर दिन लेखा-जोखा रखें कि आज आसपास या आपके घर से दूर कितने पेड़ों से आपने कीलें निकालीं, उनसे तार हटाये, उनका दम घोंट रही क्रांक्रीट अथवा सीमेण्ट को दूर किया. इसके लिये अपने पास प्लायर, कैंची, लौहे की छोटी-सी राड, खुरपी इत्यादि का एक पैकेट रखें जो अन्य कई कार्य भी आयेगा।

जीव जन्तुओ की सेवा की साप्ताहिक रिपोर्ट कार्ड -

अपनी आँखों को खुला रखकर घर से बाहर निकलें, जहाँ भी कोई पशु-पक्षी घायल, भूखा-प्यासा या अन्य किसी भी प्रकार से रोगी व ज़रूरतमंद लगे तुरंत रुककर उसे सहायता पहुँचायें, आवश्यकता पड़ने पर खुद ट्राली या ऑटो की व्यवस्था करवाकर उसे चिकित्सालय पहुँचायें. उसकी निगरानी करें व जरूरत पड़ने पर डाक्टर इत्यादि को बुलवाने का भी ख्याल रखें। वैसे भी ये कार्य करने में उतने कठिन नहीं होंगे परन्तु यदि पैसो से जुड़ी जैसी कोई समस्या या अन्य कोई बात आड़े आये तो भी परिचितों व अपरिचितों से सहायता माँगने में संकोच न करें।

बीज व वृक्षारोपण करे -

अपने साथ यहाँ-वहाँ से इकट्ठे किये गये बीज (जैसे सीताफल, बकायन, आम, चीकू, जामुन, शीशम) रखें जिन्हें आप आते-जाते मार्ग में जहाँ-जहाँ या नम व कुछ सुरक्षित-सी लगने वाले भूमि में एक छोटी-सी लकड़ी से खोदकर गड़ाते चलें जिनमें से यदि 5 प्रतिशत भी पेड़ बने तो आपका समूचा प्रयास सफल ही कहा जायेगा. स्थानीय नर्सरी से कुछ ऐसे पेड़ खरीदे जो लोगों को बहुत भायेंगे, जैसे कि तेजपत्ता, दालचीनी, मीठी नीम, कपूर, गुग्गल, अमरूद, अनार, बेलपत्र, नारियल आदि, जहाँ-तहाँ पूछताछ जारी रखें व यदि कोई भूस्वामी, मकान-मालिक, मंदिर-पुजारी या दुकानदार अपने इलाके या अधिकार क्षेत्र में वह प्रजाति लगवाना चाहे तो वहाँ स्वयं अपने हाथों से लगाकर आयें व उसकी सुरक्षा व नियमित पानी देने का निवेदन भी करके आयें. आपके द्वारा की गयी यह पहल आपके पुण्य तो बढ़ायेगी ही, साथ में हरियाली बढ़ाने के साथ सौहार्द्र बढ़ाने में भी प्रमुख भूमिका निभायेगी. यदि वृक्ष सुरक्षा-कवच बनाना हो तो तीन-चार मजबूत डण्डे, बाँस, पुरानी पड़ी राड्स गड़ाकर.. ठौंककर या गड्ढे खोदकर व रस्सियाँ या बेर-बबूल के काँटों से आप बड़ी आसानी से यह भी कर सकते हैं।

बिना स्वार्थ के कर्म करे -

स्वार्थ या अपने कुल-कुटुम्ब के लिये तो कुत्ता भी बहुत कुछ कर ही लेता है परन्तु नि:स्वार्थ भाव से या परायों के लिये, पेड़-पौधों व पशु-पक्षियों, अनाथों-बूढ़ों, अपरिचितों इत्यादि के लिये कुछ किया हो तो भगवान् को लगे कि आपको मानव जन्म प्रदान करना सार्थक हो रहा है. इस बात को समझने के लिए आप हमारा जीवन की सार्थकता के 41 मार्ग यह आर्टिकल जरुर पढ़ा जा सकता है। उपरोक्त सम्पूर्ण डाटाबेस हर दिन के आधार पर तैयार करना है, यह नहीं कि भूल गये या बाद में लिखेंगे। नया साल चाहे जब आये, आप तो अभी से आरम्भ करें, शुभस्य शीघ्रम् ! श्रीगणेश करें...

अंग्रेजी नववर्ष का भारतीयकरण

अंग्रेजी या ईसाई नववर्ष दुनियां के उन देशों में मनाया जाता है जिन पर कभी अंग्रेजों ने राज किया था। हर देश अपने इतिहास और मान्यताओं के अनुसार नव वर्ष मनाता है। भारत में प्राय: सभी संवत्सर चैत्रा शुल प्रतिपदा से प्रारम्भ होते हैं पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका और ब्रिटेन का वर्चस्व दुनियां में बढ़ गया। इन दोनों के ईसाई देश होने से कई अन्य देशों में भी ईसाई वेशभूषा, खानपान, भाषा और परपराओं की नकल होने लगी। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

एक बार फिर एक जनवरी आएगी। हर बार की तरह समाचार माध्यमों ने वातावरण बनाना प्रारभ कर दिया है। 31 दिसबर की रात और एक जनवरी को दिन भर शोर-शराबा होगा। लोगों ने एक दूसरे को बधाई लेंगे और देंगे। सरल मोबाइल संदेशों (एसएमएस) के आदान-प्रदान से मोबाइल कंपनियों की चांदी कटेंगे। रात में बारह बजे लोग शोर मचाएंगे। शराब, शवाब और कवाब के दौर चलेंगे। इसके अतिरित और भी न जाने लोग कैसी-कैसी मूर्खताएं करेंगे जरा सोचिये, नये दिन और वर्ष का प्रारभ रात के अंधेरे में हो, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है।

यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि यदि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसबर को हुआ था तो जिस वर्ष और ईसवी को उनके जन्म से जोड़ा जाता है, उसे एक सप्ताह बाद एक जनवरी से क्यों मनाया जाता है । वस्तुत: ईसा का जन्म 25 दिसबर को नहीं हुआ था। चौथी शती में पोप लाइबेरियस ने इसकी तिथि 25 दिसबर घोषित कर दी, तब से इसे मनाया जाने लगा। तथ्य तो यह भी है कि ईसा मसीह के जीवन के साथ जो प्रसंग जुड़े हैं, वे बहुत पहले से ही योरोप के अनेक देशों में प्रचलित थे। उन्हें ही ईसा के साथ जोड़कर एक कहानी गढ़ दी गयी। इससे इस संदेह की पुष्टि होती है कि ईसा नामक कोई व्यति हुआ ही नहीं वरना यह कैसे संभव है कि जिस तथाकथित ईश्वर के बेटे के दुनियां में अरबों लोग अनुयायी हैं, उसकी ठीक जन्म-तिथि ही पता न हो। जैसे भारत में 'जय संतोषी मां' नामक फिल्म ने कई वर्ष के लिए एक नयी देवी को हश्चातिष्ठित कर दिया था। कुछ ऐसी ही कहानी ईसा मसीह की भी है

इसके दूसरी ओर भारत में देखें तो लाखों साल पूर्व हुए श्रीराम और 5,000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुए श्रीकृष्ण ही नहीं तो अन्य सब अवतारों, देवी-देवताओं और महामानवों के जन्म की प्रामाणिक तिथियां सब जानते हैं और उन्हें हर वर्ष धूमधाम से मनाते भी हैं। लेकिन फिर भी नव वर्ष के रूप में एक जनवरी प्रतिष्ठित हो गयी है, लोग इसे मनाते भी हैं, इसलिए मेरा विचार है कि हमें इस अंग्रेजी पर्व का भारतीयकरण कर देना चाहिए। इसके लिए भविष्य में निन कुछ प्रयोग किये जा सकते हैं। एक जनवरी को अपने गांव या मोहल्ले में भगवती जागरण करें। अपने घर, मोहल्ले या मंदिर में श्रीरामचरितमानस का अखंड पारायण प्रारभ करें। एक जनवरी को प्रात: सामूहिक यज्ञ का आयोजन हो।

एक जनवरी को भजन गाते हुए प्रभातफेरी निकालें। सिख, जैन, बौद्ध आदि मत और पंथों की मान्यता के अनुसार कोई धार्मिक कार्यक्रम करें। एक जनवरी को प्रात: बस और रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों के माथे पर तिलक लगाएं। एक जनवरी को निर्धनों को भोजन कराएं। बच्चों के साथ कुष्ठ आश्रम, गोशाला या मंदिर में जाकर दान-पुण्य करें। ये कुछ सुझाव हैं। यदि इस दिशा में सोचना प्रारभ करेंगे तो कुछ अन्य प्रयोग और कार्यक्रम भी ध्यान में आएंगे। हिन्दू पर्व मानव के मन में सात्विकता जगाते हैं चाहे वे रात में हों या दिन में जबकि अंग्रेजी पर्व नशे और विदेशी संगीत में डुबोकर चरित्राहीनता और अपराध की दिशा में ढकेलते हैं। इसलिए जिन मानसिक गुलामों को इस अंग्रेजी और ईसाई नववर्ष को मनाने की मजबूरी हो, वे इसका भारतीयकरण कर मनाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दीं नव वर्ष की शुभकामनाएं

नईदिल्ली। देशभर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं और कामना की कि नया साल सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अंतहीन आनंद लेकर आए। सभी को बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नए साल की पूर्व संध्या पर नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि मैं आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में नई खुशियां और नया उत्साह लेकर आए। मुझे आशा है कि इस वर्ष के आपके सभी संकल्प पूरे होंगे। राजनाथ सिंह ने भी जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी है।

केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखी चिट्ठी

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर भाजपा की गतिविधियों से जुड़े कई सवाल उठाए, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या आरएसएस को लगता है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। पत्र में केजरीवाल ने भाजपा के आचरण और लोकतंत्र पर उसके प्रभाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। केजरीवाल ने भागवत से पूछा कि क्या आरएसएस अतीत में भाजपा के गलत कामों का समर्थन करता है। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा खुलेआम पैसे बांटने की प्रथा पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या आरएसएस वोट खरीदने में भाजपा का समर्थन करता है। इसके अलावा, केजरीवाल ने दलित और पूर्वांचली वोटों के बड़े पैमाने पर कटने पर चिंता जताई और पूछा कि क्या आरएसएस का मानना है कि यह लोकतंत्र के लिए सही है?

केजरीवाल को वीरेंद्र सचदेवा ने पोस्ट किया लेटर

नईदिल्ली। आगामी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे झूठ बोलने और धोखा देने की बुरी आदतें छोड़ने को कहा। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि हम सभी बचपन से ही नए साल के दिन बुरी आदतों को छोड़कर कुछ अच्छा और नया करने का संकल्प लेते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन सभी दिल्लीवासियों को आशा है कि आप झूठ बोलने और धोखा देने की बुरी आदतों को त्यागकर अपने अंदर सार्थक बदलाव लाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल से दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगने की मांग करते हुए पांच संकल्प लेने को कहा। भाजपा नेता ने केजरीवाल से झूठे वादे करना बंद करने और महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करने को भी कहा।

अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस का तीखा हमला

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर बेहद विनम्रता से बात करने और फिर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। रंधावा ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। आप पर हमला बोलते हुए उन्होंने (आप) पंजाब में कहा था कि वे महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। 3 साल में नहीं दे पाए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो उन्हें अभी दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये देने चाहिए। रंधावा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत नम्रता से बात करते हैं और फिर लोगों को धोखा देते हैं। उनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने पंजाब में लोगों को धोखा दिया है। रंधावा ने यह भी कहा कि दिल्लीवासी ऐसे मुख्यमंत्री के हकदार हैं जो उनके लिए काम करे, न कि उन्हें गुमराह करने वाला।

दिल्ली में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में बसपा

नईदिल्ली। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आप और भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। इसको लेकर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों की पहली सूची जनवरी के मध्य तक जारी होने की संभावना है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि शहर को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और सभी क्षेत्रों में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं। एक नेता ने कहा कि उम्मीदवार-चयन प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक क्षेत्र में समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। ये केंद्रीय समन्वयक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देंगे और उन्हें बहनजी (बसपा प्रमुख मायावती) को भेजेंगे। उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय इन सिफारिशों के आधार पर होगा।

साल के पहले दिन भाजपा का अरविंद केजरीवाल पर हमला

भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा, 10 सालों में वादे भी नहीं किए पूरे: सुधांशु

नईदिल्ली। भाजपा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर अपना हमला तेज करते हुए उन पर दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पार्टी ने केजरीवाल की दस प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में एक दशक रहने के बाद भी उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी 2024 में देश ने देखा। जब जेल से रहकर किसी मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया।

भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल पर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि केजरीवाल जी जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं। इसके पहले भी हेमंत सोरेन जी, मधुकोड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करूणानिधि जी... ये सब भी पद पर रहते हुए जेल गए। परंतु लालू प्रसाद यादव जी ने इतनी मर्यादा रखी थी कि उन्होंने पद छोड़ दिया था। लेकिन 2024 एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने (केजरीवाल ने) जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। त्रिवेदी ने कहा कि

आप पार्टी यह विचार लेकर आई कि हम नई राजनीति ला रहे हैं। आज की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों के बीच सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता का संकट था। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच यह धारणा बन गई थी कि राजनेता जो उपदेश देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। उन्होंने कहा क पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने इस धारणा को बदला और राजनीति में विश्वसनीयता स्थापित की। दूसरी ओर, क्क विपरीत चरम का प्रतिनिधित्व करती है, जहां वे हमेशा अपने वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतने विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप, इतने कम कालखंड में किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगे होंगे, जिसका उदाहरण आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है। उनकी पार्टी (आप) के हर वरिष्ठ नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संसद में पार्टी के नेता, तीनों जेल जा चुके हैं। आपने पहले कभी इतना विविध भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा। उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल भेजा गया, अमानतुल्ला खान को वक्फ बोर्ड में घोटाले के लिए, नरेश बाल्यान को माफिया से संबंध के लिए जेल भेजा गया।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बिजली दरें कम करने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने, स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने, स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने, लैंडफिल को हटाने, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने, झुग्गीवासियों के लिए आवास की पेशकश करने और यमुना को साफ करने का वादा किया था। हालाँकि, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने असुरक्षित बिजली तारों से राहत दिलाने का वादा किया। उनके कार्यकाल के 10 साल बाद स्थिति यह है कि 23 जुलाई 2024 को एक 26 वर्षीय युवक की इन बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। उन्होंने वादा किया था कि वह कूड़े के ढेर साफ करेंगे। हालांकि, बताया जा रहा है कि दिल्ली में कूड़े के ढेरों की ऊंचाई 8 मीटर तक बढ़ गई है।

भागवत को पत्र लिखने के बजाय आरएसएस से सेवा भाव सीखें केजरीवाल

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से कहा कि मीडिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिख 'राजनीतिक चाल' चलने के बजाय उन्हें इस स्वयंसेवी संगठन से 'सेवा की भावना' सीखनी चाहिए।

यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए त्रिवेदी ने केजरीवाल से कहा, ''संघ (आरएसएस) से सीखिए। पत्र मत लिखिए।'' उन्होंने कहा कि आरएसएस से संबद्ध सेवा भारती भारत का 'सबसे बड़ा संगठन' है जो झुग्गियों में रहने वाले दलितों सहित अन्य लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। उन्होंने कहा, ''सेवा की भावना सीखिए ऐसे संगठनों से (आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों से)। ऐसे राजनीतिक चाल मत चलिए।

तृणमूल कांग्रेस का 26वां स्थापना दिवस

लोगों के अधिकारों के लिए पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा: ममता

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बुधवार को अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी की स्थापना एक जनवरी 1998 को हुई थी। इस अवसर पर टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए पार्टी का संघर्ष जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा।

ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लिखा, सबसे पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। इसके साथ ही आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है। इस वर्ष के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपके साथ अपना लिखा और संगीतबद्ध किया एक गीत साझा कर रही हूं। यह गीत प्रसिद्ध गायक इंद्रनील सेन ने गाया है। बंगाल के लोगों के अधिकारों के लिए हमारा संघर्ष जारी है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जय हिंद! जय बांग्ला! वंदे मातरम! तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद! मां-माटी-मानुष जिंदाबाद।

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लिखा, टीएमसी देश और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं सभी टीएमसी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और बलिदान को सलाम करता हूं। वे हमारी पार्टी की रीढ़ हैं। नए साल में, आइए भविष्य के संघर्षों के लिए नए जोश के साथ तैयारी करें।

1998 में स्थापित टीएमसी 2011 में वाम मोर्चा सरकार को हराने के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी। इससे पहले 2001 और 2006 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को सफलता नहीं मिली थी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शख्सियत ममता बनर्जी ने पार्टी को लगातार तीन बार सत्ता में पहुंचाया है, जिसमें 2021 के विधानसभा चुनावों में मिली शानदार जीत भी शामिल है।

सांप-सीढ़ी की तरह रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी सफर

भोपाल। पहले कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज यानी की 01 जनवरी अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि सियासी नजरिए से देखा जाए, तो सिंधिया के लिए पिछले दो साल काफी महत्वपूर्ण रहे। अगर मध्यप्रदेश से किसी राजघराने का सबसे अधिक प्रभाव रहा है, तो वह ग्वालियर के सिंधिया परिवार का रहा है। सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के बड़े राजनेताओं में से एक हैं। तो वहीं केंद्र में भी उनका रौब बढ़ा है।

मुंबई में 01 जनवरी 1971 को ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म हुआ था। उनको सियासत विरासत में मिली थी। सिंधिया परिवार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा परिवारों में से एक हैं, जिनके पास राजशाही विरासत के साथ लोकतंत्र में रसूख भी कायम है। फिर सिंधिया चाहे कांग्रेस में हों या फिर भाजपा में, हर जगह उनका रुतबा कायम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में मध्यप्रदेश की सियासत में बड़ा सत्ता परिवर्तन किया। यह प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सिंधिया के सियासी सितारे परवान चढ़ने लगे। वहीं साल 2021 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी कद तेजी से बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद 07 जुलाई 2021 का दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सबसे अहम रहा था। इस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में जगह मिली थी। इस दौरान सिंधिया को नागरिक उड्डयन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात यह रही ज्योतिरादित्य को यहां भी विरायत मिली, क्योंकि उनके पिता माधवराव भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी टीम के अहम सदस्यों में से एक हैं और उनके जिम्मे कई अहम प्रोजेक्ट भी हैं। वहीं सिंधिया को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया।

खेल
प्रमुख समाचार

सिडनी टेस्ट के लिए रोहित के सामने सही संयोजन की चुनौती

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 1-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम के सामने सिडनी में तीन जनवरी से होने वाले अंतिम टेस्ट के लिए सही संयोजन चुनने की चुनौती है। भारत ने चौथे टेस्ट में शुभमन गिल को प्लेइंग-11 से बाहर रखा था, लेकिन जिस तरह टीम की बल्लेबाजी रही थी उससे लगा रहा है कि टीम प्रबंधन पांचवें टेस्ट में छह बल्लेबाजों के साथ उतर सकता है।

चौथे टेस्ट के बाद कप्तान रोहित शर्मा की काफी आलोचना हुई थी क्योंकि उन्होंने खुद को शीर्ष क्रम पर लाने के लिए गिल को प्लेइंग-11 से बाहर रखा था। भारत को अगर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा बनाए रखने के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल की दौड़ में बने रहना है तो रोहित को टीम के सर्वोत्तम हित में कुछ विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना होगा। भारतीय कप्तान को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर अपने छह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को उतारना पड़ सकता है जिससे मेलबर्न में पिछले मैच में बाहर किए गए शुभमन गिल को प्लेइंग-11 में शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

प्लेइंग-11 में बेहतर संतुलन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बाहर किया गया था क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी से अतिरिक्त फायदा मिलने की उम्मीद थी। वॉशिंगटन ने 50 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की और शतकवीर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ शतकीय साझेदारी भी की। अगर उनकी गेंदबाजी में अधिक पैनापन होता तो वह निश्चित रूप से अधिक ओवर फेंकते। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पारंपरिक रूप से एक ऐसा विकेट रहा है जहां मैच के आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को मदद मिलती है और इसलिए वॉशिंगटन या तनुश कोटियान में से किसी एक का रवींद्र जडेजा के साथ खेलना लगभग तय है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 368 अंक चढ़ा निफ्टी 23,743 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार (1 जनवरी) को तेजी देखी गई और नए साल 2025 के पहले दिन मार्केट हरे निशान में बंद हुई। कार मेन्युफेक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा की मंथली बिक्री में वृद्धि से ऑटो स्टॉक्स में तेजी आई और इससे बाजार को समर्थन मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बुधवार (1 जनवरी) बढ़त में खुला। हालांकि, कुछ ही देर में यह लाल निशान में फिसल गया। कारोबार के दूसरे हाफ में बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई। अंत में सेंसेक्स 368.40 अंक या 0.47त्न चढ़कर 78,507 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ह्रस्श्व) का निफ्टी-50 इंडेक्स 98.10 अंक या 0.41 फीसदी की बढ़त के साथ 23,742.90 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर सबसे ज्यादा चढ़कर बंद हुए।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक एलपीजी सिलेंडर सस्ता

नईदिल्ली। नए साल 2025 की शुरुआत में पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है1 हालांकि, यह बदलाव केवल कॉमर्शियल इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम सिलेंडर के दाम पर लागू हुआ है, जबकि घरेलू इस्तेमाल के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। 1 जनवरी 2025 से कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में औसतन 14.50 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। नई दरों के अनुसार, दिल्ली में यह सिलेंडर अब 1,804 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1,818.50 रुपये था। कोलकाता में यह 1,911 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1,927 रुपये थी। मुंबई में नई कीमत 1,756 रुपये है, जो पहले 1,771 रुपये थी और चेन्नई में यह अब 1,966 रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत 1,980.50 रुपये थी।

रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएफओ लॉन्च

नईदिल्ली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड के लॉन्च करने की घोषणा की है, जो ग्रामीण और संबद्ध थीम पर आधारित ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण भारत की वृद्धि और विकास में योगदान देने वाले और उससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में निवेश करेगी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण और संबद्ध क्षेत्रों में शामिल कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जुटाना है। एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 9 जनवरी 2025 को खुलेगा और 25 जनवरी को बंद होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के एनएफओ के फंड मैनेजर संकरन नरेन ने कहा, ग्रामीण भारत अगला विषय है, जो अगले दशक में परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है। हमारी नई स्कीम का लक्ष्य इन विकासों का लाभ उठाना है, जिससे निवेशकों को भारत की ग्रामीण विकास कहानी में भाग लेने का मौका मिल सके।

इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ पर टूट पड़े निवेशक

नईदिल्ली। इंडो फार्म इक्विपमेंट के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को निवेशकों से जोरदार रिस्पांस मिला है और सब्सक्राइब करने के दूसरे दिन अब तक 31 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ अप्लाई करने के लिए मंगलवार (31) दिसंबर को खुला था। यह 2 जनवरी को सब्सक्राइब करने के लिए बंद होगा। इंडो फार्म इक्विपमेंट ने आईपीओ खुलने से पहले सोमवार (30 दिसंबर) को एंकर निवेशकों से 78 करोड़ रुपये जुटाए। साल 2024 आईपीओ के लिहाज से शानदार साबित हुआ है। नए साल 2025 में भी आईपीओ मार्केट में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच, 2024 का आखिरी आईपीओ इंडो फार्म इक्विपमेंट भी अच्छी कमाई का इशारा कर रहा है। कंपनी ने अपने पब्लिक इश्यू के लिए प्राइस बैंड 204 रुपये से 215 रुपये प्रति शेयर तय किया है।

रुपए की तीव्र गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती

भारतीय रुपए के लिए यह एक उथल-पुथल भरा समय रहा है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से कदम रख रहा है, ताकि इसे 'व्यवस्थित' विनिमय आंदोलन के रूप में देखा जा सके। 19 दिसंबर को रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 85 के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले शुक्रवार को यह 86 के स्तर के करीब पहुंच गया था, लेकिन केंद्रीय बैंक द्वारा देर से हस्तक्षेप करने पर यह 85.53 पर वापस आ गया।

हाल के दिनों में कई कारकों ने रुपए को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें सितंबर के अंत में प्रमुख सूचकांकों के चरम पर पहुंचने के बाद प्रतिभूति बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का निरंतर बहिर्वाह शामिल है। अत्यधिक स्टॉक मूल्यांकन, जुलाई-सितंबर तिमाही में निराशाजनक कॉर्पोरेट प्रदर्शन और चीन के आर्थिक प्रोत्साहन ने उभरते बाजारों के पोर्टफोलियो को मुंबई से बीजिंग की ओर धकेल दिया।

डोनाल्ड ट्रम्प के कारक ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के बाद डॉलर के मजबूत होने के साथ एक नई बाधा उत्पन्न की और वैश्विक व्यापार में यू.एस. डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक आम मुद्रा योजना के लिए ब्रिक्स देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ की उनकी चेतावनी से उभरते बाजार की मुद्राएं और भी अधिक हिल गईं। व्यापार मामलों पर ट्रम्प के आमतौर पर संरक्षणवादी रुख के बारे में आशंकाओं के साकार होने से पहले ही, भारत की वस्तु व्यापार कहानी लडखड़ा रही है। रिकॉर्ड व्यापार घाटे और आयात बिल इस तिमाही के चालू खाता घाटे में दिखाई देंगे, जो दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.2 प्रतिशत से दोगुना होने की उम्मीद है। सेवा व्यापार अभी

भी अधिशेष दे रहा है, लेकिन एच-1बी वीजा व्यवस्था के आसपास अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण निगरानी योग्य होगी, ट्रम्प की प्रणाली पर नवीनतम शांत टिप्पणियों के बावजूद।

पिछले आर.बी.आई. गवर्नर, शक्तिकांत दास ने ब्रिक्स मुद्रा को केवल 'एक हवा में विचार' के रूप में खारिज करके अच्छा किया और जोर देकर कहा कि भारत का कोई डी-डॉलरीकरण एजेंडा नहीं है। सरकार को भी सार्वजनिक मंचों और कूटनीतिक वार्ताओं में इस आशय का एक स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए, ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। यह सच है कि अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं को बड़ा झटका लगा है और गिरता हुआ रुपया निर्यातकों के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन भारत को आयात मुद्रास्फीति के बारे में भी चिंता करने की जरूरत है, खासकर खाद्य तेल और कच्चे पैट्रोलियम जैसी अलोचदार वस्तुओं पर। इसके अलावा, विदेशी निवेश प्रवाह अनिश्चित है, जैसा कि 2025 के लिए अमरीकी मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण है।

रुपए के प्रक्षेपवक्र को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को किस हद तक तैनात कर सकता है, इसकी भी एक सीमा है और वित्त मंत्रालय ने माना है कि हाल ही में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव मौद्रिक नीति निर्माताओं की स्वतंत्रता को बाधित करता है। भारत की वर्तमान आर्थिक परेशानियां घरेलू कारकों, जैसे कि कम होती खपत और अनिच्छुक निवेश से जुड़ी हैं। रुपए के दबाव में आने के साथ, 2025 में देश की बाहरी लचीलेपन की भी परीक्षा हो सकती है और नीति निर्माताओं को इस नए जोखिम से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

ग्रीन जीडीपी के लिए बना देश का पहला राज्य

नये साल में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि

रायपुर। नये साल की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रचा है। नये साल 2025 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ में विकास की गति को आगे बढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विज़न और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें वन विभाग नेसंचालित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन की अवधारणा शामिल है। यह समग्र दृष्टिकोण राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन न केवल बजटीय योजना को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा, बल्कि भविष्य की रणनीतियों को दिशा प्रदान करेगा, धन आवंटन को अधिक प्रभावी बनाएगा और वानिकी विकास के प्रयासों को सशक्त करेगा। यह प्रक्रिया सतत विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

छत्तीसगढ़ में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। स्थानीय निवासियों को जंगल सफारी, नेचर ट्रेल्स और इको-कैंपिंग जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, जिससे न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सशक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार हैं और लाखों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं।

वनों से प्राप्त होने वाले अन्य महत्वपूर्ण अमूर्त लाभ अक्सर उपेक्षित रहते हैं और उनका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। इनमें जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बन अवशोषण, कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परागण, पोषक तत्वों का चक्रण, मृदा उर्वरता में सुधार और जैव विविधता संरक्षण जैसी सेवाएं शामिल हैं। वनों का बाढ़ और रोग नियंत्रण, जल प्रवाह का प्रबंधन और वेक्टर जनित रोगों के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं वनों से जल पुनर्भरण और शुद्धिकरण होता है, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, और सुंदर प्राकृतिक दृश्य तथा जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान होती है। इन वनों का गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि पवित्र स्थलों और देवगुड़ी जैसे क्षेत्रों के माध्यम से ये आदिवासी विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वन अनेक नदियों का उद्गम स्थल हैं, जो सतत जल प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और कृषि तथा आजीविका के लिए आवश्यक जैविक पदार्थ से मृदा को समृद्ध करने में सहायक हैं। इन प्रत्यक्ष लाभों का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

बाबू भैया की कलम से ✍

प्रशासन के हवा हवाई प्रतिबंध और टूटती बंदिशे, ऐसी क्या मजबूरी

अंग्रेजी वर्ष 2024 की बिदाई और 2025 के आगमन का जश्न बड़े धूमधाम से पूरे देश के साथ छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मनाया गया। प्रशासन ने शासन के आदेश पर अनेक प्रतिबंध राजधानी के बड़े लोगों के होटलों पर लगाए। जो हश्र उन आदेशों का राजधानी में हुआ,वही हश्र प्रदेश के सभी होटलों में हुआ ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध था शराब परोसने का समय, यह तय किया गया था कि 12 बजे रात के बाद शराब नहीं पिलाई जाएगी। 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। नाबालिगों को शराब नहीं दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? रात भर शराब दी गई,डीजे तब तक बजता रहा जब तक लोग झूमते रहे। सुबह की रोशनी कब आई किसी को होश नहीं। नाबालिगों को धड़ल्ले से शराब परोसी गई। सारा नजारा देख कर तो ऐसा लग रहा था कि होटल मालिकों को किसी का कोई डर ही नहीं था। सच भी है कि ''सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का'' अनेक होटल मालिकों से सरकार में बैठे दिग्गजों से सीधी पहचान ,संबंध और दोस्ती जग जाहिर है। जब सरकार ही अपनी व अपनों की हो तो डरने का प्रश्न ही नहीं है। रोकने - देखने का अधिकार जिन्हें था वे दिखावा करने गए जरूर , पर शायद चढ़ावा लेकर चले आये कुछ तो वहीं पार्टी का हिस्सा भी बन गए। इसी बहाने परिवार को भी बड़े होटल का दर्शन करा दिया। रात गुलजार होती रही ,मय के प्याले टकराते रहे,पर्दादारी भी समाप्त हो गई। सरकार में बैठे लोगों ने अपने परिवार में नववर्ष मनाया,किस तरह मनाया,यह उनका निजी जीवन का मामला है। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। लोग चर्चा करते रह गए कि शराबबंदी की हिमायती पार्टी की सरकार होने के बाद होटलों को शराब पिलाने की अस्थाई अनुमति क्यों और किस नियम की तहत दी गई,क्या मजबूरी थी। 80 लोगों ने अनुमति मांगी थी। किस नियम की तहत अस्थाई अनुमति दी गई किसी के समझ में नहीं आया। 80 में से 70 को ऐसी शर्तों के साथ अनुमति दी गई जिसका पालन किसी ने भी नहीं किया। 10 को किस कारण छोड़ दिया? मॉनिटरिंग क्या हुई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अनुमति देकर आंख बन्द क्यों व किस कारण की गई। ये सारे प्रश्न अनुत्तरित ही रहेंगें। किसी पर कार्यवाही हुई इस बात का पता लगाना भी मुश्किल काम है। प्रतिबंध के बाद भी इतना खुला खेल कैसे खेला गया ? यह समझने वाली बात है। अब रात गई बात गई वाली कहावत सच्चाई में बदली जाएगी। लोग कहते हैं , जब शासन -प्रशासन के पास बंदिशों को लागू करने की शक्तियां नहीं है,तो ऐसी बंदिशों को लागू ही क्यों करती है। गणेश - दुर्गा पूजा की झांकियों के दौर में भी बंदिशों को लागू करने में शासन-प्रशासन असफल रहा था। कहा गया कि कानफोडू डीजे का शोर नहीं होगा फिर जो हालात देखे गए ,वो सबके सामने हैं। डीजे की कानफोडू आवाज जानलेवा साबित हो चुकी है। एक बुजुर्ग की मौत डीजे की भारी धमक के कारण हुई थी। प्रशासन ने कड़ाई का निर्णय लिया पर कड़ाई कर नहीं पाई। प्रशासन को चंद दिग्गजों की सिफारिशें भारी पड़ गई। वही हुआ जो होना था ,डीजे की आवाजों ने फिर अनेकों के दिल की धड़कनों को तेजी से धड़काने का काम किया। इस बार फिर नए साल के जश्न के पहले अनेक बंदिशें लगाने का सरकारी ऐलान हुआ,अखबारों में प्रचार हुआ कि प्रशासन ने कड़ाई करने का कड़ा निर्णय लिया है। किसी को कोई छूट का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रशासन दावे करता रहा और लोग उसे तोड़ते दिखाई दिए। शासन -प्रशासन लाचार देखता रह गया,जो होना था वो धड़ल्ले से हुआ। पांच हजार से एक लाख तक के एंट्री पास इन होटल ,रिसोर्ट,रेस्टोरेंटों में खुले आम बेचे गए। सरकार के खजाने में एक पैसा भी टैक्स का नहीं आया। कोई देखने झांकने भी नहीं आया। जीएसटी का कहीं आता पता नहीं, सब फ्री। जानकारी के अनुसार ललित महल में 2699 रु. मेरा रिसोर्ट में 10000 रु.,होटल हयात में 10000 रु.,होटल बेबीलोन में 5500 रु.,कोर्टयार्ड मेरियट में 10000 रु., होटल सयाजी में 5000 रु. और भी अन्य होटलों रेस्टोरेंट व रिसोर्ट में जनता से जम कर राशि वसूली गई। वो भी पास बेचकर। सरकारी विभागों की नजर होते हुए भी कुछ नहीं किया गया। लाखों रु. के टैक्स का नुकसान सरकार के खजाने को हुआ है। कौन इसकी भरपाई करेगा। बिना पास कहीं भी एंट्री नहीं दी गई। धड़ल्ले से पैसा लिया गया ,वो भी काउंटर से पास बेचकर लिया गया। कहीं भी मुफ्त एंट्री नहीं दी गई। आबकारी,जीएसटी,प्रशासन व पुलिस प्रशासन की टीम कहीं भी जांच करने नहीं घुसी या घुसने से रोकने की व्यवस्था कर दी गई थी,यह समझने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बंदिशें लागू करने में पहले भी शासन -प्रशासन असमर्थ दिखाई दे चुकी हैं,तो ऐसी बंदिशों का प्रचार प्रसार करके अपनी पीठ क्यों थपथपाती हैं। जो कुछ भी चल रहा है वैसे भी तो चल ही रहा है। यानी जो है वो तो हइये है।

बीजेपी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में 30 सहायक शिक्षक गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर में 30 सहायक शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तार बिना अनुमति रैली लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तोड़फोड़ करने के तहत किया गया है. माना पुलिस ने इन शिक्षकों के खिलाफ प्रतिबन्धक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है.बता दें, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी संविदा सहायक शिक्षकों की पात्रता ना होने के चलते सेवा समाप्ती के आदेश दिये थे, जिसके बाद इन शिक्षकों ने आक्रोशित हो कर आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने परिसर में तोड़फोड़ कर दी. इसके चलते रायपुर की माना पुलिस ने इन्हें प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

ननि चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले की नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु दिनांक 1 जनवरी 2025 के प्रति निर्देश से मतदाता सूचियां तैयार करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है, । इसी परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी देने हेतु जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन बिलासपुर के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2025 को आयोजित की गई बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी गई कि जारी कार्यकम अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 31दिसंबर 2024 को किया गया है। प्रारंभिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों पर दावे एवम आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी तक प्राप्त की जायेगी । साथ ही दिनांक 01जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा की वर्तमान में प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज है, वे नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने हेतु पात्र होगे तथा ऐसे मतदाता निर्धारित प्रारूप क-1 में आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिनांक 10 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकते है।

चिकित्सा महाविद्यालय में 18 चिकित्सा शिक्षकों का संविदा नियुक्ति, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए एक साथ 18 चिकित्सा शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज रायपुर में पहली बार एक साथ इतने संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। डॉ. रूमी कुमार, सहायक प्राध्यापक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, डॉ. हर्षिता भाटिया सहायक प्राध्यापक रेडिएशन अंकोलॉजी, डॉ. कमलकांत साहू, सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक मेडिसीन, डॉ. स्निग्धा कुमारी सहायक प्राध्यापक (कार्डियक निश्चेतना) सीटीव्हीएस विभाग, डॉ. रचना रिची पांडेय सहायक प्राध्यापक (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभाग, डॉ. अविनाश बंजारे (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभग, डॉ. श्रुती तूरकर सहायक प्राध्यापक (एनेस्थिसिया) क्रिटिकल केयर, डॉ. संध्या वर्मा सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी, डॉ. रेबिना यादव सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी विभाग, डॉ. प्रिंशी चौधरी सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. पियूषी साव सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. सुरभि चौबे सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. पारूल राठी सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. शुभांगन मिश्रा सीनियर रेसीडेंट प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉ. नील पसरीजा सीनियर रेसीडेंट अस्थि रोग, विनय मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनजुम मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनुराग संचय कालकुलेवर रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स की चिकित्सा शिक्षक के रूप में संविदा नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सरकार के किसान विरोधी रवैय्ये से धान खरीदी ठप्पः बैज

रायपुर। धान खरीदी शुरू हुये डेढ़ माह बीत गये लेकिन सरकार अभी तक धान खरीदी केन्द्रो की व्यवस्था सुधार नहीं पाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार के किसान विरोधी रवैय्ये के कारण अभी तक लक्ष्य का आधा धान ही खरीदी हो पाया है। किसानों को अपना धान बेचने के लिये परेशान होना पड़ रहा है। परिवहन और मिलिंग के अभाव में सोसायटी में जगह नहीं है टोकन नहीं कट रहा इस कारण धान खरीदी ठप्प पड़ी है। अंतिम एक माह में लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो पायेगी इसमें भी संशय है।जिन किसानों ने धान बेच भी दिया है। उनको भुगतान के लिये परेशान होना पड़ रहा है। 3100 रू. के स्थान पर मात्र 2300 के दर से भुगतान हो रहा है। उसमें भी एक साथ पैसा नहीं मिल रहा। वह भी तीन चार किस्तो में दिया जा रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय किसानों को 3100 रू. धान की कीमत देंगे तथा गांव में काउंटर बना कर एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। भाजपा अपना वह वादा भी नहीं निभा रही। किसानों को न 3100 रू. की कीमत मिल रहा न एकमुश्त भुगतान हो रहा, न ही किसी पंचायत में भुगतान का काउंटर बनाया गया है।

शिक्षकों को बर्खास्त किया जाना निंदनीय : शुक्ला

रायपुर। सरकार द्वारा बीएड डीग्रीधारी 2897 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार का यह अविवेकपूर्ण और तानाशाही रवैया है इन शिक्षकों की बर्खास्तगी साय सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय कदम है। सरकार चाहती तो इन शिक्षकों की नौकरियां बचाई जा सकती है। हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि इन शिक्षकों की फिर से बहाली किया जाए। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में जब से बनी है तब से युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनकी लगी नौकरी छीनने का काम कर रही है। शिक्षक बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए थे लेकिन वहां उनके साथ बदतमीजी की गई रोते हुए शिक्षकों को मारा गया, पिटा गया। इन 2897 प्रभावित शिक्षकों में से लगभग 70 प्रतिशत शिक्षक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। मुख्यमंत्री स्वयं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, लेकिन दलीय चाटुकारिता में भी गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश के युवाओं के हक और अधिकारों में डाका डाला जा रहा है।

सरकार के संरक्षण से खुलेआम परोसी जा रही शराबः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में शराबखोरी को बढ़ावा दे रही है। नए साल जश्न आयोजित करने वाले होटल, ढाबों, रिसोर्ट को शराब पिलाने की अनुमति दी, पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर की रात को जगह-जगह शराब पिलाई जा रही थी। इससे भाजपा सरकार की शराब के प्रति प्रेम छलका है। पुलिस प्रशासन जहां एक ओर चौक चौराहा पर बेरियर लगाकर नशा करके वाहन नहीं चलाने जागरूकता अभियान चलाती है, वहीं दूसरी ओर शराब खोरी के लिए सरकार परमिशन देती है, ऐसे में शराब पीने वाले सड़क पर आएंगे ही और जब दुर्घटना होगी, हत्या या अन्य प्रकार की घटनाएं होगी उसकी जवाबदेही कौन लेगा? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा विपक्ष में रहते शराब बंदी की मांग को लेकर आंदोलन करते रही है और सरकार में आते ही शराब के बिक्री को बढ़ाने रोज नई-नई तरकीब अपना रही है। पहले शराब दुकानों के बगल में खुलने वाले अहातों को वाताअनुकूलित किया, सुविधाजनक बनाया। फिर लोगों को मनपसंद शराब पिलाने के लिए ऐप लॉन्च किया ताकि लोग अपने मनपसंद शराब सरकार के किस दुकान में कहां पर मिल रहा है।।

दो-दो बजरंगियों की हत्या पर भी मौन, विवशता है या डरः वर्मा

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 27 से 31 दिसंबर 2024 तक 5 दिन के दौरे पर रायपुर में रहे और इसी दौरान नशाखोरी और चाकूबाजी के चलते राजधानी में दो-दो बजरंगियों की हत्या हो गई। संघ को परिवार बताने वाले संघ प्रमुख पीड़ित के परिजनों से मिलना तक जरूरी नहीं समझे। सत्ता सुख में इतने मस्त रहे की संघी बजरंगियों की निर्मम हत्या पर भी ख़ामोशी अख्तियार कर लिया। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, सरेआम सड़कों पर अपराधी दौड़ा-दौड़ा कर चाकू मार रहे है, पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। इस सरकार में संघी, भाजपा और बजरंगी तक सुरक्षित नहीं है। दुखद है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर में रहते हुए भी पीड़ित बजरंगी परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक बयान तक नहीं दे पाए। आखिर पीड़ित बजरंगी परिवारों के प्रति संवेदनहीनता का क्या कारण है, भाजपा सरकार का दबाव है या मोहन भागवत की कोई मजबूरी?प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार का फोकस केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है, जिसके चलते प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार फल-फूल रहे हैं।

हिमालय के शिखर पर लहराया छत्तीसगढ़ चैंपियंस लीग टी 21 का ध्वज

रायपुर। आगामी फरवरी माह में प्रदेश भर में आयोजित होने वाली पेशेवर क्रिकेट प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ चैंपियंस लीग टी21 का ध्वज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालय की खूबसूरत वासियों और ऊंची पर्वत श्रृंखला केदारकांठा के समिट प्वाइंट 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर लहराया गया। वीर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बतलाया कि 20 किलोमीटर के इस ट्रैक को 3 दिनों की कठिन चढ़ाई चढ़कर वे समिट प्वाइंट पर पहुंचे थे और 1 जनवरी की सुबह माइनस 5 डिग्री तापमान पर ध्वज लहराया।

ज्ञात हो यह क्रिकेट प्रतियोगिता बीते 2 सीजन छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के नाम से सफलता पूर्वक आयोजित की जा चुकी है तथा इस वर्ष नए नाम और फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश की 8 टीमें बनाई जायेगी जिनके मध्य रायपुर, बिलासपुर और भिलाई स्टेडियमों में मुकाबले खेले जाएंगे।

जल जीवन मिशन ▶ कार्यों में तेजी लाने नए साल के पहले ही दिन डिप्टी सीएम साव उतरे फील्ड पर

मल्टी-विलेज योजना से 50 गांवों में पहुंचेगा पेयजल : साव

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने आज नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। वे आज राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामाखेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय एनीकट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेकवेल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना के इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग-डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों का काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांवों में टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकासखंड के 50 गांवों के 15 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाय एनीकट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। करीब 75 करोड़ रुपए लागत की इस योजना का 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। योजना का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना का भी अवलोकन किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी।

बिल्हा से धान खपाने टिकारी ले जा रहे दो ट्रैक्टर पकड़ाए, वाहन समेत 224 बोरी धान जब्त

बिलासपुर। धान के अवैध संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। मस्तुरी तहसील के ग्राम वेद परसदा में धान ले जाते दो ट्रैक्टर पकड़ाए। दोनों में 224 बोरी धान ले जाया जा रहा था। धान की कीमत लगभग 2.78 लाख बताई गई है। राजस्व, खाद्य और मंडी के अफसरों की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। जाँच के दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त धान बिल्हा से विक्रय हेतु ग्राम टिकारी तहसील मस्तुरी ले जाया जा रहा है। उपरोक्त धान के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज यथा-धान परिवहन हेतु अनुमति आदेश, मण्डी शुल्क, धान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मौके पर उपस्थित वाहन चालकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त धान के उपार्जन केन्द्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए वाहन एवं उसमें भण्डारित 224 कट्टी (बोरी) धान को तहसीलदार द्वारा जप्त करते हुए प्रकरण निर्मित कर मण्डी अधिनियम के तहत् नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जावेगी। उल्लेखनीय है कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान उपार्जन केन्द्रों में धान व्यापारियों और कोचियों द्वारा अवैध रूप से धान को खपाने संबंधी क्रिया-कलापों पर कडी निगरानी रखने एवं उन पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है।निर्देशों के परिपालन में जिले में राजस्व, खाद्य एवं मण्डी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध धान के भण्डारण एवं परिवहन किये जाने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही जारी है। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोचियों और दलाल किस्म के लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीम ने मजबूत सूचना तंत्र बना रखा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.